www.twnews.in / RNI No.UTTHIN/2015/68784 हिन्दी मासिक पत्रिका

टाईम विटनेस

सभी देश व प्रदेशवासियों को ईद-उल-अजूहा, स्वतंत्रता दिवस व रक्षबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं -सम्पादक

वर्ष:5 अंक :01 अगस्त 2019 मूल्य : रू 15/-

क्योंकि हम उठायेंगे आपकी आवाज!

अनुच्छेद 370

जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित राज्य

लद्दाख
केंद्र शासित राज्य

अच्छे भविष्य की कयास

समस्त प्रदेश व देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

डी.एस. मान

चैयरमेन

दून इंटरनेशनल स्कूल

समस्त प्रदेश व देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

समीर पुण्डीर

ग्राम प्रधान चालंग,

न्यायपंचायत गुजराड़ा

॥ ॐ ब्रह्म सत्यम ॥

विश्वनाथ कोहली

प्रदेश अध्यक्ष

उत्तराखण्ड स्वर्णकार संघ

अजय कोहली

संजय कोहली

सभी देश व प्रदेश वासियों को

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

STANDARD JEWELLERS

59, Dhamawala Bazar,

Dehradun (U.K.)

Ph.: (S) 2651285

New STANDARD JEWELLERS

Subhash Nagar,

Dehradun (U.K.)

Ph.: (S) 2640127

Deal in : Gold, Diamond, Silver, Birth Stones & Platinum

www.standardjewellers.co.in , E-mail : kholiajay@gmail.com

समस्त प्रदेश व देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

अभिषेक पंत

पार्षद, वार्ड 60 डांडा लखौंड

समस्त प्रदेश व देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

पंकज मैसोन

युवा नेता, भाजपा उत्तराखण्ड

PRAYAG IAS Academy

Uttarakhand's Leading Institute for IAS/PCS, PCS (J)
Prayag IAS College Maan Singh Waala,
Dehradun, Ph. No. 0135-2744550

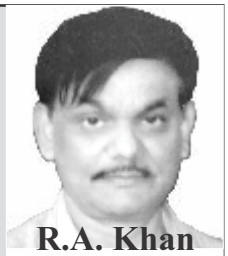

R.A. Khan
Director

आरएनआई संख्याः UTTHIN/2015/68784

टाईम विटनेस

मासिक पत्रिका वर्षः 5 अंक : 01

अगस्त 2019

सह संरक्षक	डॉ. संजय गांधी
विशेष सलाहकार	विजय खण्डूड़ी
कानूनी सलाहकार	मनमोहन कण्डवाल (एडवोकेट)
संपादक	अफरोज़ खाँ
गढ़वाल प्रभारी	अशोक रावत
पछवादून प्रभारी	संजय कुमार
व्यवस्थापक	भुपेन्द्र चौहान, मेघराज सिंह राठौर
एनसीआर प्रभारी	ए.के. राना
ब्यूरो चीफ, देहरादून	इकराम अंसारी
संवाद्दाता	बाबू हसन
लेआउट डिजाइनर	शिखा बिष्ट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अफरोज खाँ द्वारा प्रितिका प्रिंटर्स, 9 प्रगति विहार, धर्मपुर, देहरादून से मुद्रित कराकर, शर्मा कॉलोनी, ब्राहमण्वाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।

संपादक अफरोज खाँ

पत्रिका से संबंधित किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला- देहरादून ही मान्य होगा।

अन्दर के पृष्ठ में

6 **दून को चंडीगढ़ सा बनाने की चाह**

10 **लाल किले से पानी, पर्यावरण और जनसंख्या की गूंज**

16 **फैलती दुनिया, सिमटते सरोकार, सोशल मीडिया का मक्कड़जाल**

पंजीकृत कार्यालय टाईम विटनेस

शर्मा कॉलोनी, ब्राहमणवाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड
मो0 7409293012, 9084366323
ई-मेलः timewitness2015@gmail.com,
afrojkhan78600@gmail.com

नोटः जरूरी नहीं कि लेखक के लिखे लेख से सम्पादक सहमत हो, एवं सभी पद परिवर्तनीय है व सभी सदस्य अवैतनिक है।

लोकतंत्र पर हावी भीड़तंत्र

72 साल आते-आते बहुत कुछ बदल गया है। अब संसद में बहुमत के द्वारा कोई भी कानून बनाया जा सकता है चाहे वह लोकतांत्रिक, समाजिक या न्यायकि दृष्टि से सही हो या नहीं

आजादी के 72 साल पूरे हो गये हैं और इन 72 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अग्रंजी शासन से एक लम्बे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 में देश अजाद हुआ, जिसमें देश के कई स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की आहूत देते हुये शहीद हो गये। देश आजाद होने के साथ ही राजशाही भी खत्म हो गई और हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, यानी राज्यों से बना लोकतांत्रिक देश, जिसमें हर किसी को अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहने की आजादी मिली। सत्ता में रहने वाली पार्टी की विचारधारा से नहीं बल्कि लोकतंत्र की नीति व मूल्यों पर चलने की आजादी मिली, इसलिए संविधान भी बना, जिसमें केवल धर्मनिरपेक्षता को ही जगह नहीं दी गई, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एव कारोबार करने का संवैधानिक अधिकार भी मिला। लेकिन 72 साल आते-आते बहुत कुछ बदल गया है। अब संसद में बहुमत के द्वारा कोई भी कानून बनाया जा सकता है चाहे वह लोकतांत्रिक, समाजिक या न्यायकि दृष्टि से सही हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं अब तो देशद्रोही और देशभक्त खुद ही तय कर दिया जा रहा है, बस 'भीड़तंत्र' साथ होना चाहिए, बाकि किसी की भी फरवाह नहीं। 'भीड़तंत्र' यह वह तंत्र है जो अब लोकतंत्र पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत जनता को एक बिना सोच वाली भीड़ में तब्दील कर दिया गया है। जिसे बस जरा-सी अफवाह की जरूरत है वह बिना सोचे समझे किसी को भी पीट-पीटकर मार डालती है। जो सवाल उठाए उसे ही आतंकवादी, भ्रष्टाचारी या फिर देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 2016 में दलितो के खिलाफ हिंसा में 840 मामले हुये है, लेकिन इन मामलों में सजा की दर में कमी आई है। एक नेशनल न्यूज पोर्टल के अनुसार 4 साल में 134 मामले मॉब लिंचिंग के हुये, इन गंभीर मुद्दो पर जवाब दने की बजाया भीड़ हिंसा पर सवाल उठाने वालों को ही आतंकवादी, अलगावादी एवं 'टुकड़े-टुकड़े गैंक' का सदस्य बताकर उन पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप मढ़ा जा रहा। अब सवाल यह है कि देश में भीड़तंत्र का न्याय चलेगा या लोकतंत्र का? इस मसले पर सार्थक बहस देश के लिए बहुत जरूरी।

कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स

एक अनमोल रिश्ता | सोना, चांदी के जेवरातों के विक्रेता

अब बेटी की शादी के जेवर की चिंता छोड़ें कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स से नाता जोड़ें

68 माजरा, सहारनपुर रोड, दहेरादून फोन न0 0135-2726569, मो. : 9837359716

समस्त प्रदेश व देशवासियों को

ईद-उल-अज़हा व

स्वतंत्रता दिवस

एवं रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

हाजी सुलेमान अंसारी

प्रदेश सचिव, उत्तराखण्ड कांग्रेस

एवं पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी

समस्त प्रदेश व देशवासियों को

ईद-उल-अज़हा

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक

शुभकामनाएं

एन.एस. बिंद्रा

पूर्व अध्यक्ष

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक

आयोग

समस्त प्रदेशवासियों को

ईद-उल-अज़हा

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

हार्दिक शुभकामनाएं

शहताब चौधरी

समाजसेवी

सभी देश व प्रदेशवासियों को

ईद-उल-अजहा

स्वतंत्रता दिवस

व रक्षाबंधन की

दिली मुबारकबाद

हाजी सलीम अहमद

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अ०स० मोर्चा, भाजपा

दून को चंडीगढ़ सा बनाने की चाह

अशोक रावत
गढवाल प्रभारी

देहरादून को अब चंडीगढ़ की तर्ज पर चमकाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग गलियों में सिकुड़ती जा रही सड़कों से मुंह फेर कर शुरुआत चौराहे से की जा रही है, पर यहां गाड़ी फंस गई। भूमि अधिकरण से लेकर कई सरकारी व निजी भवन और कई दुकाने गले की हड्डी बन गए हैं। मेयर बनने के बाद सबसे पहले सुनील उनियाल गामा ने कहा की मेरी पहली प्राथमिकता शहर की साफ सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की होगी उसके लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई जाएगी। हर वार्ड में डोर–टू–डोर कूड़ा उठाया जाएगा, ताकि शहर साफ सुथरा दिखाई दे। दूसरा दून को स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा करेंगे।

मेयर साहब पहले राजधानी को यानि दून को उन फुटपाथ पर दुकानदार द्वारा सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा है, उस फुटपाथ को खाली कराए जो सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके बनाए हैं और वे जनता के पैदल चलने के लिए हैं, ना कि दुकानदार के सामान के लिए जो कि पूरे दून के फुटपाथ पर काबिज हैं। एक या दो दिन हटाने से काम नहीं चलता मेयर साहब जनता देख रही है कि आप दून में अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ–साथ कुछ और काम भी देखना जरूरी है, जैसे कि आए दिन जाम ही जाम कहीं से भी नहीं लगता कि यह उत्तराखंड की राजधानी है, जिधर देखो जाम। प्रशासन ने भी हर तरह के उपाय करके देख लिया दो–चार दिन चलता है, फिर वही ढाक के तीन पात और कभी तो ट्रैफिक पुलिस का प्रयोग उल्टा पड़ जाता है।

शहर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाम से निजात मिलती हो। दूसरी वजह यह भी है, कि फुटपाथ पर दुकानदार के सामान तथा

जो गाड़ी खड़ी करने की जगह वो तो दुकानदारों व मॉल मालिकों ने गोदाम बना रखे हैं। यह हमारी प्रशासन वह एमडीडीए की लाचारी है कि वह खाली नक्शे पास करने के सिवा और कोई काम नहीं है

वहां खड़े होने के कारण ही जाम की वजह है, वजह एक और भी है दून में अधिकतर दुकानें व शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में, जो की पार्किंग के लिए है वहां पर समान तथा जनरेटर लगे हैं, इसलिए ग्राहक अपनी गाड़ी भी बाहर ही सड़क पर खड़ी करते हैं लेकिन आज तक ना तो प्रशासन तथा ना एमडीडीए ने इसकी सुध ली। पिछले दिनों जब एमडीडीए और पुलिस संयुक्त टीम ने आईएसबीटी से लेकर सब्जी मंडी तक 24–25 कॉम्लेक्स तथा होटलों का निरीक्षण किया तो पार्किंग की जगह गोदाम और दुकान मिली, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तो मात्र 20–25 दुकानों का हाल है तो पूरे दून का क्या हाल होगा? जो गाड़ी खड़ी करने की जगह वो तो दुकानदारों व मॉल मालिकों ने गोदाम बना रखे हैं। यह हमारी प्रशासन वह एमडीडीए की लाचारी है कि वह खाली नक्शे पास करने के सिवा और कोई काम नहीं है।

स्मार्ट सिटी के परियोजना के तहत दून शहर की काया पलट सकती है, इसके लिए उच्च संचालक समिति के बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर यहां तक सबसे पुराने बाजार पलटन बाजार की भी काया पलट सकेगी। जिस तरह हाल के दिनों में भीड़भाड़ बाजार के बीच मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अन्य वाहन चलते हैं, उसके बाद सुबह 7:00 बजे से रात तक यानी 10:00 बजे तक कोई भी गाड़ी न आ सकेगी, ना जा सकेगी, सिर्फ यह सुविधा बुजुर्ग गर्भवती महिला के लिए छूट की सुविधा होगी। जिस तरह जाम से निजात दिलाने के लिए दून में फ्लाईओवर बनाए वह तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन इसमें से 1–2 फ्लाईओवर चर्चा में बहुत रहे जैसे कि बल्लीवाला का फ्लाईओवर, जो शुरू से ही विवादों में रहा। पहले तो इस फ्लाईओवर का शिलान्यास कांग्रेस सरकार के समय में जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसके उद्घाटन के लिए कांग्रेस तथा भाजपा के नेता आपस में ही फ्लाईओवर पर नेम प्लेट लगाने के लिए भिड़ गये और दोनों गुट के नेता अपने पार्टी के झंडे लेकर पहुंच गए। किसी तरह मामला शांत हुआ तो फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद जो हादसे हुए इन हादसों में 10–12 लोगों की जान चली गई, जो हमारी कार्यशैली में बहुत ही बदनुमा दाग है, पहले तो इसका डिजाइन जो कि कागजों में था, वह धरातल पर नहीं दिखा, इसके बाद इस फ्लाईओवर की चौड़ाई काफी कम है, यानी दो गाड़ी ओवरटेक करने में असमर्थ है, क्योंकि पुल की चौड़ाई कम होने के कारण यह हादसे हुए। फिर भाजपा–कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता एक–दूसरे पर आरोप लगाने लगे, पहले तो इन नेताओं को यानी जिस की भी सरकार हो या रही हो इन नेताओं को यह सोचना चाहिए कि यह हादसे क्यों हुए, फिर जैसा डिजाइन था वह जमीन पर क्यों नहीं बना, इसका क्या कारण था? अगर कोई भी नेता अपना वोट बैंक बचाने के लिए फ्लाईओवर के डिजाइन में कुछ बदलाव किया तो, क्या इस नेता या पार्टी के विरोध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए थी या नहीं? फ्लाईओवर का खाली मुद्दा बनाना या सिर्फ फ्लाईओवर में 5–6 स्पीड ब्रेकर बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ऐसा कौन–सा फ्लाईओवर होगा और है जिसमें स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हो, यह एक मजाक ही बना है, क्योंकि फ्लाईओवर पर हर रोज सैकड़ों गाड़ी गुजरती होगी, इसमें से कुछ गाड़ी अन्य प्रदेशों की भी होगी, वे क्या सोचते होंगे कि उत्तराखंड में एक ऐसा फ्लाईओवर भी है जिसमें की 20–25 की स्पीड से गाड़ी निकलती है, जबकि फ्लाईओवर पर 60–80 की स्पीड से गाड़ी निकलती है इसको कहते हैं फ्लाईओवर।

दूसरी ओर बात करते हैं शहर की नालियों की जो कि राजधानी के बीचो–बीच यानी चूना भट्टा अन्य नाली तथा चूना भट्टा सर्वे चौक के तरफ से निकलती हुई नाली इतनी बहती है कि आम आदमी वहां से निकल नहीं सकता, जबकि राजधानी के बीचो–बीच में स्थित है, फिर भी नगर निगम इन दुकानदारों को सिर्फ देखकर आंखें बंद कर लेता है। वहीं प्रेमनगर से लेकर बल्लुपुर चौक तक आए दिन जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 18–33 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब यह कब बनाई जाएगी यह आने वाले समय में देखा जाएगा। दूसरी तरफ छटे फ्लाईओवर की तैयारी की जा रही है, जो कि भंडारी बाग से टेस्ट कैंप को जोड़ने के लिए 800 मीटर लंबा होगा। इनके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए रेल विभाग के पास भेज दिया है।

राजधानी दून में जल्द ही ऐसी बसे होंगी जो फर्राटा भरेंगी। यह बसें 26–40 सीटों वाली

ब्लडबैंक के पास नाले में इकट्ठा होता गांदा पानी और काले घेरे में पीने के पानी का पाईप।

होगी, यह बसें इलेक्ट्रिक होगी, यह सुबह 6:00 से रात के 9:00 बजे तक चलेगी। इन बसों का अड्डा आईएसबीटी होगा। अधिकारियों ने बताया कि यह बसें आईएसबीटी से रेलवे स्टेशन, घंटाघर, जाखन, सुद्दोवाला, प्रेमनगर, रायपुर तथा जौली ग्रांट एयरपोर्ट से घंटाघर तक चलेगी।

दून में आए दिन अतिक्रमण हटाने के बीच दुकानदारों व नगर निगम के कर्मचारियों में नोकझोंक कोई नई बात नहीं है इसका कारण है। सिर्फ एक दो दिन प्रशासन का डंडा चलता अगर यह काम हर दिन चले और प्रशासन शांत ना हो तो दुकानदारों की क्या मजाल है कि फुटपाथ या रोड पर समान लगा ले, लेकिन यहां तो एक दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती है और फिर टायं–टायं फिश। सिर्फ सामान जब्त करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर वही सामान 500–1000 रूपये देकर छूट जाता है 500–1000 रूपये की रसीद काटकर नगर निगम अपना पल्ला झाड़ लेता है, यह तो तब

ब्लडबैंक के पास नाला बना गले की हड्डी

अब बात करते हैं ब्लड बैंक के पास नगर निगम द्वारा किये गये कार्य का, जब कोई भी काम तरीके से नहीं होगा उस काम का यही हाल होगा जो आजकल ब्लडबैंक के पास पानी की टंकी से ठीक सटे हुये सड़क किनारे दो-तीन साल पहले से नाला बना, आज गले की हड्डी बना है। बरसात का पानी निकासी ना मिलने के कारण नगर निगम तथा प्रशासन के इस नाले को साफ करने में पसीने छूट रहे हैं। नाले के सामने दो रेस्टोरेंट का मलवा (कचरा) भी उसी नाले में डाला जाता है, क्योंकि वह एक रसूखदार मालिक के रेस्टोरेंट है, तो किसकी क्या मजाल कि कोई कार्रवाई कर सके, वैसे तो उस नाले को साफ करने के लिए उस क्षेत्र के पार्षद के कहने पर नाली साफ कराई, दूसरी तरफ दूसरे पार्षद ने। अब दोनों ही एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते इसलिए एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मजे की बात है कि रेस्टोरेंट के लिए जनता के पीने की पानी वाली पाइप लाइन को तोड़ दिया गया है तथा जब उन्हें जोड़ा गया तो, आप अगर उस पानी की लाइन को देख लोगे तो आप पानी पीने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार यानी स्वच्छ व सुंदर दून की बात करने वाले, पीने के पानी की लाइन को देखकर तो शायद वह यह बात नहीं करेंगे।

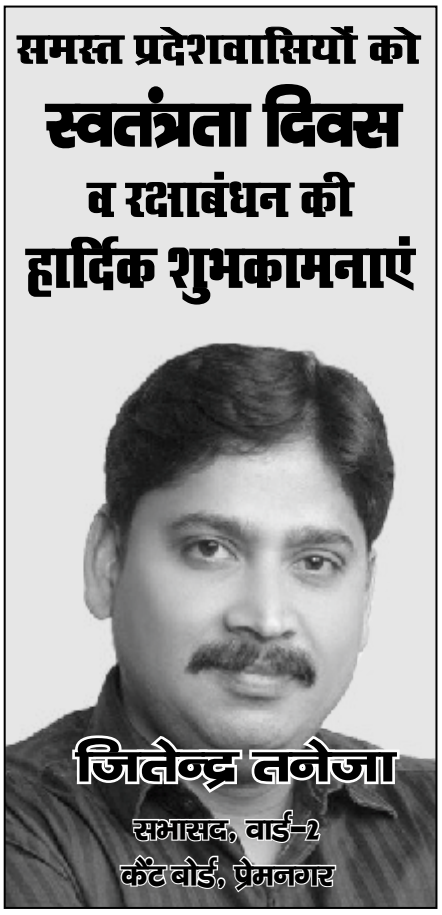

हो रहा है जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। अगर हाईकोर्ट सख्ती ना दिखाता तो आने वाले समय में सड़क पर गाड़ी चलने की बात तो छोड़ो आदमी पैदल भी नहीं चल सकता था।

दून शहर की सुंदरता बिगाड़ने में हमारे ही अपने पूर्व पार्षद तथा वर्तमान पार्षदों के साथ पूर्व विधायक तथा वर्तमान विधायकों का ही हाथ है। अपनी वोट बैंक की रोटियां सेकने के चक्कर में नेताओं ने ही दून की सुंदरता बिगाड़कर रख दी है। आज जो हाल दून का है वह जनता से छिपा नहीं है।

बिन्दाल नदी जो शहर के बीचोंबीच है यहां भी लोग अतिक्रमण करके बस गए हैं, उनका क्या हाल है पूरा दून जानता है। पहले तो इस नदी में गरीब लोगों को बसाया फिर इन लोगों से शहर के बीच में नशे का सामान बिकवाया जाता है। आए दिन लोगों को पुल के नीचे तथा पुल के ऊपर तक नशे का सामान लाते, ले जाते देखा जा सकता है। इनका मुखिया कौन है? कौन इसको ला कर देता है, जबकि बिंदाल चौकी मात्र सौ से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर है, फिर भी खाली खानापूर्ति के नाम पर कार्रवाई होती है, सिर्फ दिखावे के लिए कार्यवाही होती है, छापा मारा जाता है। अगर सीएम रावत जी कार्रवाई करें तो हर गलत काम बंद हो सकता है। वैसे तो दून की सुंदरता बिगाड़ने में पूर्व मेयर भी पीछे नहीं रहे, उनको यह नहीं पता था कि नगर निगम में क्या हो रहा है? खाली सीट पर बैठने से कुछ नहीं होगा। शहर में काम भी करना पड़ता है आज जो भी दून की हालत है उसके लिए हमारे ही नेतागण जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर पूर्व मेयर चाहते तो दून को सूंदर दून, स्वच्छ दून, बना सकते थे, जिसके लिए कभी देहरादून जाना जाता था। आज जो हालात हैं ऐसा लगता है कि किसी देहात कस्बे में आ गए हैं। जब से सुनील उनियाल गामा ने मेयर की सीट संभाली है तब से थोड़ा बहुत दूर की सुंदरता दिख रही है जैसे कि आए दिन सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाना, सफाई कर्मचारियों को सुपरवाइजर द्वारा देखना, चेतावनी देना, अगर दून में सफाई व्यवस्था को बिल्कुल चाक–चौबंद करना है तो कर्मचारी गायब मिले या सफाई में कमी रहती है तो सीधा सुपरवाइजर पर तुरंत एक्शन हो, जिस तरह से शहर में कनक चौक से लेकर चूना भट्टा तक कहीं भी किसी की दुकानों के पास गंदगी मिली तो सीधी कार्रवाई होगी तथा शहर में डेरी पर भी गाज गिरनी तय है। इसी तरह अगर पूर्व मेयर ने थोड़ी सी भी अपनी कुर्सी की लाज रखी होती तो आज हमारे दून की यह दुर्दशा नहीं होती। जिस तरह गामा जी काम कर रहे हैं और आगे करते रहे तो इन 5 सालों में दून की कुछ तो हालत सुधरेगी। जिस तरह नगर निगम का हाल था बिना पैसे लिए कोई भी काम ना करना, दफ्तर आने का कोई टाइम नहीं, जनता को पता नहीं कि साहब दफ्तर आएंगे भी कि नहीं। नगर निगम भगवान भरोसे चल रहा था लेकिन जिस तरह मेयर सुनील उनियाल गामा ने नगर निगम को सुधारने का मुद्दा उठाया है, तो लगता है दून की जनता को लग रहा होगा कि हमने सही आदमी को चुना है, ऐसा ही अगर दून या उत्तराखंड के सभी कर्मचारी तथा अधिकारी काम करें तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री को बार–बार कहना ना पड़े कि देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और हमारे प्रदेश तरक्की करेंगा तथा खुशहाल रहेंगे।

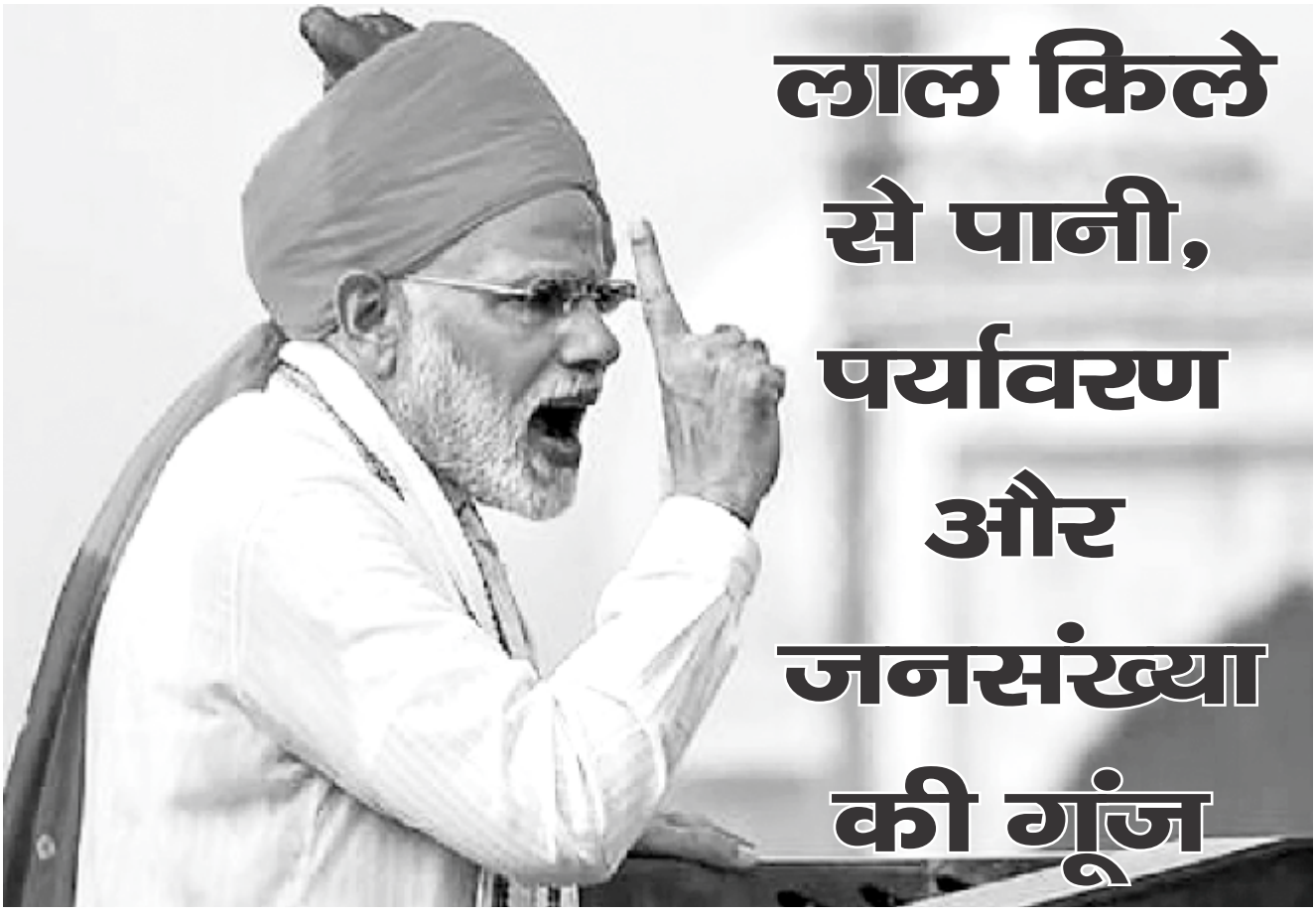

लाल किले से पानी, पर्यावरण और जनसंख्या की गूंज

सुशील कुमार सिंह
(शिक्षाविद्, लेखक,
स्तम्भकार,
मोटिवेशनल स्पीकर)
निदेशक,
प्रयास आईएएस स्टडी
सर्किल, देहरादून।

मानव सभ्यता के विकास को जिन कारकों ने प्रभावी किया उन्हें लेकर लाल किले की प्राचीर से 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शिद्दत से छूने का प्रयास किया। स्वतंत्रता दिवस क्या चिन्हित करना चाहता है इसकी भी झलक भाषण में साफ–साफ दिखी। सामान्यतः ऐसा रहा है कि लाल किले से ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री अधिकतर अपनी सरकारों के कामों का बखान करते देखे गये हैं। मगर इसी लाल किले से स्वच्छता, शौचालय, पानी, पर्यावरण, वातावरण समेत जनसंख्या विस्फोट व प्लास्टिक बैन समेत बुनियादी विकास के प्रसंगों का वर्णन शायद ही सुनने को मिला हो। 94 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम संवेदनशील मुद्दों को छूने का प्रयास किया। किसानों और व्यापारियों को मिलने वाली मदद की चर्चा और यह कहना कि अब सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। वाकई ऐसा लगा कि मानो एक नये भारत की सोच और समझ को पुख्ता करने का प्रयास किया गया है। इसमें दुविधा नहीं कि सरकार कई आषाओं पर खरी उतरी है इसलिए उसे बहुत कुछ कहने का हक है। निराशा को आशा में बदलने का काम दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ मोदी ने शीघ्र शुरू कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति देना और अनुच्छेद 370 और 35ए से जम्मू कश्मीर को आजादी देना जिसमें कि जोखिम और साहस दोनों का मिश्रण था वाकई सरकार का बेहतरीन प्रदर्शन कहा जायेगा। वन नेशन, वन इलेक्शन वैसे तो चर्चा पहले से है पर लाल किले से इसकी भी गूंज सुनने को मिली। गूंज तो वन नेशन, वन टैक्स वाले जीएसटी की भी एक पूरक के तौर पर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और गैर जरूरी कानूनों का खात्मा जो कि मोदी सरकार का मिशन है यह भी भाषण में बाकायदा शामिल था।

गौरतलब है कि पिछले पांच सालों में 1450 गैर जरूरी कानून सरकार ने खत्म किये हैं। दूसरी पारी को अभी बामुश्किल ढ़ाई महीना ही बीते हैं 60 कानून अभी तक खत्म किये जा चुके हैं। स्पष्ट है कि सरकार ईज़ ऑफ लिविंग को आसान बनाना चाहती है। इतना ही नहीं 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा चुकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने बड़ा रूप देने का मन बना लिया है। लाल किले से

श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आतंक के परिप्रेक्ष्य को लेकर मोदी ने पड़ोसी पाकिस्तान को घसीटना नहीं भूले। हालांकि पाकिस्तान को इस बार वैसा नहीं ललकारा जैसा कि मोदी की प्रकृति में है।

ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की चर्चा कमोबेश पहले के भाशणों की भांति ही सुनाई दी। शांति और सुरक्षा विकास के अनिवार्य पहलू हैं। विश्व शान्ति के लिए भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी जैसी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इस अवसर पर दोहराया। इसके अलावा जीवन के उन संवेदनशील पहलुओं को भी मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर चेताना नहीं भूले। जिस पर यह देश, दुनिया टिकी रहेगी। भाषण के दौरान 130 करोड़ जनसंख्या में उन्होंने यह परोसने की कोशिश की कि पानी की बचत, पर्यावरण का संरक्षण और प्लास्टिक को नकारने का अब समय आ गया है। इतना ही नहीं जनसंख्या विस्फोट का उनके भाषण में होना यह संकेत देता है कि सरकार इस ओर भी अब अपनी चिंता झुका रही है।

पड़ताल बताती है कि 2014 में पहली बार लाल किले से बोलते हुए मोदी 70 मिनट खर्च किये थे। साल 2015 में 86 मिनट, 2016 में 92 मिनट, 2017 में 57 जबकि 2018 में 82 और अब 2019 में 94 मिनट के भाषण से लाल किले की प्राचीर से जो गूंज उठी उसने भारत समेत दुनिया को बेहतरीन और प्रगाढ़ संदेश देने का काम किया। इन्हीं भाषणों में बुनियादी और संवेदनशील मद्दे उठे जिनको जमीन पर उतारने का काम जारी है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आतंक के परिप्रेक्ष्य को लेकर मोदी ने पड़ोसी पाकिस्तान को घसीटना नहीं भूले। हालांकि पाकिस्तान को इस बार वैसा नहीं ललकारा जैसा कि मोदी की प्रकृति में है। इतना ही नहीं विरोधियों को भी बहुत ज्यादा आड़े हाथ नहीं लिया। शायद एक मजबूत सरकार के तौर पर मोदी ये समझ रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए व्यवधानों को पहचानना है, उन्हें दूर करना है न कि बेफजूल की राजनीति में वक्त जाया करना है।

भाषण के सभी हिस्से अपने ढंग से वजनदार हैं पर कुछ मुद्दे व्यापक अवधारणा से युक्त देखे जा सकते हैं। पानी और पर्यावरण पर चिंता, प्लास्टिक पर बैन की बात और जनसंख्या विस्फोट इस स्वतंत्रता दिवस के मौलिक विचार कहे जा सकते हैं। गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशन की कुछ साल पहले की रिपोर्ट में था कि यदि विश्व के देशों ने पानी बचाने के उपायों पर काम नहीं किया तो आने वाले 15 वर्षों में पूरी दुनिया को 40 फीसदी पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह अवधि 2030 तक समझी जा रही है। यदि हालात ऐसे बने रहे तो करीब दो दषक बाद आज की तुलना में पानी आधा रह जायेगा। भारत की आबादी पहले स्वतंत्रता दिवस से 73वें तक में लगभग 4 गुनी बढ़ चुकी है जबकि पानी की खपत के मामले में यह 800 फीसद की बढ़त ले चुकी है स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की लाल किले से पानी को लेकर प्रकट की गयी चिंता बेवजह नहीं है। दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों से प्रति वर्ष भूमिगत जल 4 फीट नीचे की ओर जा रहा है। खबर यह भी है कि चेन्नई में भूमिगत जल का खजाना खाली हो गया है। प्रधानमंत्री ने पानी को लेकर एक पुस्तक का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें लिखा गया था कि सौ साल बाद पानी किराने की दुकान में बिकेगा जो आज हो रहा है। देखा जाये तो पानी और पर्यावरण एक–दूसरे के पूरक हैं जब पर्यावरण बचेगा तभी जल भी बचेगा। गौरतलब है कि पर्यावरण में भी असंतुलन बाढ़ लिये है। भारत में वन प्रतिषत बामुश्किल 21 फीसदी के आसपास है जबकि यह 33 फीसदी होना चाहिए। रिपोर्ट तो यह भी है कि जो ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं वे 2030 तक काफी पैमाने पर सिकुड़ जायेंगें। तपिष के चलते हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल आग से स्वाहा हो जाते हैं। नीति आयोग भी कहता है कि 75 फीसदी घरों में पीने के पानी का संकट जबकि 70 फीसदी पानी प्रदूषित है। अभी तो पानी खत्म होने की सूचना चेन्नई से है पर दिल्ली, हैदराबाद समेत 21 शहर में जल्दी भूमिगत जल खत्म हो जायेगा जिसके चलते 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान में जिस जीडीपी को दहाई के आंकड़े तक पहुंचाना चाह रहे हैं वही गिरते जल स्तर के कारण 2050 तक 6 फीसदी नुकसान में जा सकती है। तब तक देश की जनसंख्या 150 से 180 करोड़ की हो सकती है। स्पष्ट है कि इस जनसंख्या विस्फोट से कई समस्याएं विस्फोटक रूप ले लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पावन पर्व जनसंख्या पर चिंता जाहिर करके यह संकेत दे दिया है कि यदि आने वाली पीढ़ियों को अनेक संकटों से बचाना है तो इसके प्रति जागरूक होना ही होगा। पानी और पर्यावरण के साथ प्लास्टिक भी बुनियादी समस्या बन चुकी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि दिल्ली में हर रोज़ 690 टन, चेन्नई और कोलकाता में 429 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है जो स्वास्थ और पर्यावरण दोनों का दुश्मन हो। प्रधानमंत्री ने इस पर भी चिंता जाहिर करते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत की अवधारणा पेश कर दी है और कपड़े के झोले की नीति को आगे बढ़ा दिया है। लोगों को सचेत किया और दुकानदारों को इस पर एक्शन लेने का सुझाव भी जताया है। फिलहाल 73वां स्वतंत्रता दिवस शौर्य और साहस के साथ 74वें की प्रतीक्षा में देशवासियों को आगे करके स्वयं पीछे हो गया। देश सभी का है ऐसे में यह बात शिद्दत से समझनी होगी कि लाल किले से जो गूंज उठी है वह किसी नेता का भाशण नहीं है बल्कि देश के उत्थान और स्वयं के विकास के लिए चुनौती से भरी गौरवगाथा है।

आर्टिकल 370

अच्छे भविष्य की कयास

ऐसी समस्याएं जोर-जबरदस्ती से नहीं, अंततः संवाद से हल होती हैं

5 अगस्त 2019 को जम्मू–कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा और एतिहासिक फैसला लिया गया। राष्ट्रपति के आदेश के बाद मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के उन सभी प्रवाधानो को हटा दिया गया जो जम्मू–कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, और खुद का संविधान, ध्वजा और नागरिकता का अधिकार देता था। इसके साथ ही 35ए स्वतः समाप्त हो गया, जिसमें कश्मीर में कोई भी गैर कश्मीरी सम्पत्ति नहीं खरीद सकता, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता था।

भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने के साथ ही जम्मू–कश्मीर को दो हिस्सो में बांट दिया है और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक होगा लद्दाख दूसरा होगा जम्मू–कश्मीर। दोनों प्रदेशो का शासन उप राज्यपाल करेंगें। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू–कश्मीर में विधानसभा होगी। अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग बिल्कुल विरोध में हैं। अब इसके हटने से आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा यह तो भविष्य में ही पता चलेगा।

क्या है 370

भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जम्मू–कश्मीर की रियासत, जो आजाद रहना चाहती थी, तब तक भारत में शामिल नहीं हुई जबकि पाकिस्तानी 'कबाइलियों' ने उस पर हमला नहीं कर

दिया। अक्टूबर 1947 की विलय की संधि की शर्तों में महाराजा हरि सिह ने कहा– जिस पर भारत राजी हुआ कि कश्मीर प्राथमिक तौर पर रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामलों को भारत की संसद के हवाले करेगा और बाकी सभी क्षेत्रों के लिए राज्य की सहमति की दरकार होगी।

विलय की संधि का अनुच्छेद 7 वास्तव में क्या कहता है, ''इस संधि की कोई भी चीज मुझे किसी भी तरह से भारत के भविष्य के किसी भी संविधान को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगी या भविष्य के ऐसे किसी संविधान के तहत भारत सरकार के साथ नई व्यवस्था कायम करने से नहीं रोकेगी।'' अनुच्छेद 370 संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया और इसने भारत के राष्ट्रपति को संविधान के कुछ विशिष्ट हिस्सों को जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से वहां लागू करने की शक्ति दी। अनुच्छेद 370 में यह भी कहा गया कि इन कानूनों को राज्य की संविधान सभा के सामने रखना होगा– 'वैसे फैसलों के लिए जो यह वहां ले सकता है'– इसका अर्थ था कि राष्ट्रपति के आदेश के मामले में आखिरी निर्णय लेने की शक्ति वास्तव में राज्य की संविधान सभा के पास थी।

चूंकि अनुच्छेद 370 को अस्थायी उपबंध के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए कुछ लोग यह कल्पना कर लेते हैं कि यह संविधान की बुनियादी संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) नहीं है. हकीकत यह है कि हां, इसे हटाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा, जिसने ऐसा न करने का निर्णय लिया और इस तरह से इसे स्थायी बना दिया। अनुच्छेद 370 काफी सचेत तरीके से तैयार किया गया और विचार–विमर्श के बाद बनाया गया प्रावधान था, जिसका मकसद भारतीय संघ में जम्मू–कश्मीर के स्थान को उन शर्तों के आधार पर जिसके तहत इसने भारत में विलय पर सहमति जताई थी, को पक्का करना था।

बहरहाल, कश्मीर का हल आसान नहीं है, उसकी अपनी जटिलताएं हैं। लेकिन इतिहास का इकलौता सबक यही है कि ऐसी समस्याएं जोर–जबरदस्ती से नहीं, अंततः संवाद से हल होती हैं, जनता का कॉलर पकड़ कर नहीं, उसके हाथ थाम कर हल होती हैं।

मिलता रहेगा विशेष अनुदान

जम्मू एवं कश्मीर में विशिष्ट संवैधानिक दर्जे के खात्मे के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर विशेष अनुदान की वित्तीय व्यवस्था बनी रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90 फीसदी अनुदान और 10 फीसदी रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलेगी। 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार, दोंनों नए केंद्रशासित प्रदेशों को स्पेशल फंड भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर भी सशर्त प्रतिबंध जारी रह सकता है।

नहीं दिखी लोकतान्त्रिंक प्रक्रिया

एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 बिना विपक्ष के चर्चा के हटा दिया गया, उसमें दूर–दूर तक लोकतंत्र का नामो निशान नजर नहीं आया। जिस जम्मू–कश्मीर के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया गया, वहां की जनता तक को इसके बारे में पता ही नही चला, और न ही उनसे इस विषय पर बात की गई। साथ ही वहां की नेताओं सहित जनता को अपने–अपने घरो में नजरबंद कर दिया गया, मोबाईल व इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई।

जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए : मनमोहन सिंह

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का सरकार का फैसला देश के अधिकतर लोगों की अभिलाषा के अनुसार नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर भारत के विचार (आईडिया ऑफ इंडिया) को जीवंत रखना है तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत गहरे संकट से गुजर रहा है इसलिए समान विचार वाले लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, 'देश की अधिकांश जनता की अभिलाषा का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। महत्वपूर्ण है कि इन सभी लोगों की आवाज सुनी जाए। हम केवल अपनी आवाज उठाकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि दूरगामी रूप से भारत का विचार जीवंत रहे, जो हमारे लिए बहुत पवित्र है।'

कश्मीर से कन्याकुमारी तक का वह नारा

रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब 'इंडिया आफ्टर गांधी' में इस बात का जिक्र किया है कि कश्मीर की संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू–कश्मीर को लेकर तीनों विकल्पों की बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर जिस तरह की ताकतों से घिरा है, उन्हें देखते हुए वह आजाद नहीं रह सकता। पाकिस्तान में जाने के विकल्प को उन्होंने इस आधार पर खारिज किया कि वहां के सामंत और जमींदार कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें नेहरू से उम्मीद है कि वह अपने यहां की कठमुल्ला ताकतों को परास्त कर सकेंगे और कश्मीर का भविष्य भारत में है. गुहा की किताब यह भी बताती है कि यह शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का वह नारा दिया था जो आज भी भारत की एकता को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

नोटबंदी व जीएसटी की तरह ना हो हालत

संसद में गृहमंत्री अमीत शाह ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने से वहां के लोगो का तेजी से विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होंगे, आतंकवाद का सफाया होगा। यही बात उस समय भी कही गई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के समय किया था। मगर जो इस समय के देश का हालात है वह तो सबके सामने हैं।

पैसा ये पैसा है कैसा

दीप शिखा

पैसे की ताकत को कम मत समझना जनाब,
ये वो बला है जो हर रिश्ते में आग लगा देती है।
पैसे से आज इंसान की पहचान है,
वरना ये दुनिया हम जैसे गरीबो को भूला देती है।।

पैसे की ताकत से हमने रिश्तो को बनते बिगड़ते देखा है,
पैसा है तो सब अपना समझते है।
और अगर पैसा नहीं तो लोग कहेंगे,
हमने तुमको कभी नहीं देखा है।।

आज इस पैसे का शिकार हम भी होकर आए हैं,
अपनो के बीच अजनबी की जिंदगी गुजार आए है।
मत पूछो साहब पैसे की खातिर,
जब कोई अपना आपको रुला देता है,
अपना जन्म ही सजा का एहसास दिला देता है।।

पैसा है तो दूर के रिश्ते भी नजदीक नजर आते है,
पैसा नहीं तो लोग खून के रिश्ते भी भूला देते हैं।
पैसा है तो रात में भी उजाला है,
अगर पैसा नहीं तो पूरा जीवन ही काला है।।

इस पैसे ने तो जमाने का ये हाल बना दिया है,
पैसे के कारण कुछ लोगो ने अपने माँ-बाप को वृद्धा आश्रम तक पहुँचा दिया है।।

प्रेमजाल में फंसाकर युवतियों को किया जा रहा ब्लैकमेल

उत्तराखण्ड में युवतियों से दुर्व्यहार, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग का मामला बढ़ गया है, इसी विषय पर एक खास बातचीत में गुरू फॉरेंसिक एण्ड डिटेक्टिव एजेंसी के चेयरमैन विजय खण्डूड़ी ने हमे बताया कि उनके पास भी ऐसी काफी शिकायते आ रही हैं, जिसमें कोई व्यक्ति किसी महिला या युवती को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके बदले पीड़ित युवतियों से मोटी रकम मांगी जा रही है। कई युवतियां तो हमारे पास मदद के लिए भी आ चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि जब हमने इसका पता लगाया तो इसके कई वजह सामने आये, जिसमें से एक सबसे सामान्य कारण यह है कि आजकल उत्तराखण्ड में कुछ ऐसे लोग सक्रिय है, जो युवतियों को पहले तो अपने प्रेमजाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनकी नीजी पलो की तस्वीरे या वीडियो बना लेते हैं, फिर खेल शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का।

विजय खण्डूड़ी ने बताया कि जब किसी महिला की निजी पलो की फोटो या फिर अश्लील विडियो उसका प्रेमी बना लेता है तो वह महिला डर और बदनामी के वजह से इस बात को किसी से नहीं कह पाती, इसी का फायदा उठाकर वह युवक उसको ब्लैकमेल करता रहता है। और उसके बदले उस पीड़ित युवती से मोटी रकम वसूलता है, या फिर उसका शोषण करता रहता है। साथ ही पीड़ित युवती को धमकाया भी जाता है कि अगर उसने यह बात किसी से कही या पुलिस के पास गई तो वह यह विडियो सोशल मीडिया पर वायरल

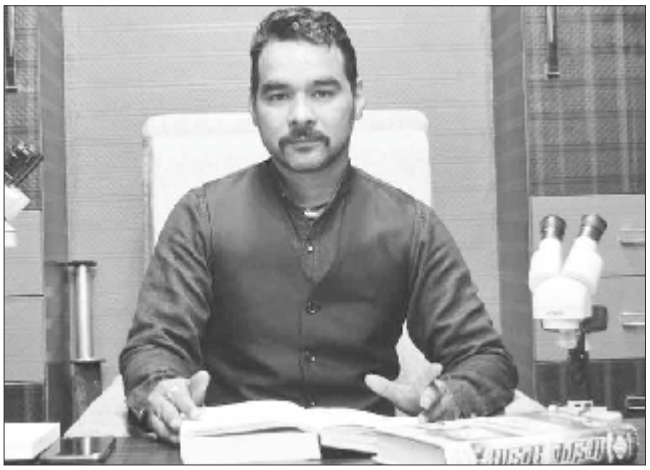

कर देगा, जिसकी वजह से पीड़ित महिला चुप रहती है।

खण्डूड़ी ने कहा कि ऐसे में पीड़ित युवतियों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके डर की वजह से ही ऐसे लोगो का हौसला बढ़ता है। युवतियों को ऐसे मामालो में खुलकर बोलना चाहिए और पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पीड़ित युवती जो इस तरह के मामले में फंसी हो वह हमसे भी मदद ले सकता है। हमारी उस युवती को मदद देने की पूरी कोशिश रहेगी।

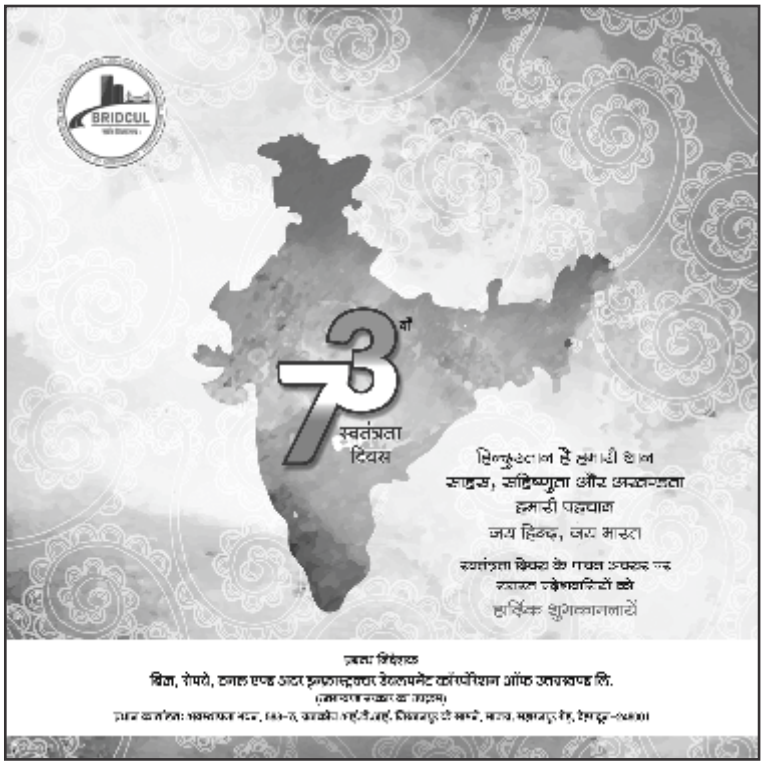

Mob: 9027728192

FABRICATION

All type of stainless steel, M.S. & Aluminium work

- All type of Fancy Gates, SS & MS
- Light Fabrication
- Railing & Windows in SS & MS
- Tin shades ✦ Wall Papers
- PVC Doors & PVC Panels
- Modular Kitchen
- All type of Glass work

पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को बहाल करने के लिए कानून बनायेगी सरकार

उत्तराखण्ड की त्रिवेंद्र सरकार अब कानून बनाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को बहाल करेगी। गुपचुप तरीके से लाए गए इस प्रस्ताव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सरकारी किराया दरों पर आवास के साथ निशुल्क चालक सहित वाहन, ओएसडी, टेलीफोन सहित तमाम सुविधाएं देने का प्रावधान कर दिया गया है। 13 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी जा चुकी है। अब ये विधेयक विधायी विभाग के जरिये राजभवन जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। आने वाले दिनों में जब विधानसभा सत्र होगा, तो उसमें सरकार विधेयक लेकर आएगी और कानून बनाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को कानूनी जामा पहनाएगी।

एक याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूल करे। इसके बाद सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया वसूली का नोटिस जारी कर दिया था। इस मामले में दो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। न्यायालय ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो कोश्यारी पर सरकार का 47 लाख रुपये और बहुगुणा पर 37 लाख रुपये किराया बकाया है। प्रदेश सरकार जो अध्यादेश लाई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ी राहत दी गई है। मसलन, इस अध्यादेश के प्रभावी होने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को समस्त सुविधाएं (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) दी जाती रहेंगी। आवास आवंटन की तिथि से सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही किराया वसूला जाएगा।

यानी उन्हें बाजार दर से किराया नहीं देना होगा। अध्यादेश के प्रभावी होने के साथ ही किसी अन्य अधिनियम या न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश या दिशा-निर्देश लागू नहीं होगा। दूसरी बड़ी राहत यह है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों का समय-समय पर कराये गए मरम्मत कार्य का खर्च वहन नहीं करना होगा, बल्कि ये सरकार स्वयं उठाएगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को यदि पेंशन, भत्ता या अन्य सुविधाएं देय हैं तो वे उसके हकदार होंगे। बिजली, पानी, एवं सीवर शुल्क भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं संबंधित विभाग को दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री को वैयक्तिक सहायक१ विशेष कार्याधिकारी१ जनसंपर्क अधिकारी, चालक के साथ वाहन, वाहन के लिए पीओएल, वाहनों में मरम्मत कार्य, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार और माली, टेलीफोन अटेंडेंट और सुरक्षा गार्ड मिलेगा।

एक याचिका पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए थे कि वो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूल करे।

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार

Website :www.ukmadarsaboard.org.in
Email ID - ukmadarsaboard@gmail.com

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा किए गए कार्य

1. वर्ष 2019 में अरबी फारसी परीक्षाएं प्रदेश के जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में कुल 13 राजकीय इंटर कॉलेजों में उनके प्रधानाचार्यों के संचालन में आयोजित की गई। जिसका मूल्यांकन कार्य भी सी0सी0टी0वी0 कैमरों की निगरानी तथा राजकीय प्रवक्ताओं की देखरेख में संपन्न हुआ।
2. प्रदेश में अरबी फारसी बोर्ड परीक्षा 2019 में कुल 5746 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनका परीक्षा फल 92.38 प्रतिशत रहा। उक्त परीक्षाओं का परीक्षाफल मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री यशपाल आर्य जी के द्वारा 4 जून 2019 को विधानसभा सभागार में मीडिया की उपस्थिति में जारी किया गया।
3. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, के ''स्वच्छ विद्यालय पहल'' योजनान्तर्गत 90 मदरसों में 425 पृथक–पृथक बालक/बालिका शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
4. दिनांक 19.07.2019 को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याण भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राज्य समन्वयक, श्री इंद्रेश कुमार जी द्वारा प्रतिभाग कर पौधारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न मदरसों द्वारा भी पौधारोपण किया गया।
5. राज्य निर्माण के उपरान्त मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शासन के निर्देशन में 56 मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु नितान्त आवश्यक है।
6. एस.पी.क्यू.ई.एम. तथा आई.डी.एम.आई. योजनाओं को एकीकृत करते हुए एस.पी.ई.एम.एम. (Schem for providing education in Madarsas/Minority) योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।

a- SPQEM:- उक्त योजनान्तर्गत मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए प्रत्येक स्तर हेतु 3 शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं। जिनमें ग्रेजुएशन (स्नातक) शिक्षकों को रु. 6000/– एवं पोस्ट ग्रेजुएशन (स्नातकोत्तर) शिक्षकों को 12000/– प्रति माह भारत सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है

b- IDMI:- मदरसों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए योजना संचालित है, जिसमें मदरसों में कक्षा–कक्षों एवं लाइब्रेरी आदि का निर्माण किया जाता है।

c- अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 से 5:00 बजे तक कार्यालय में आकर अथवा दूरभाष सं0 0135–2781157 पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अखलाक अहमद
उप रजिस्ट्रार
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून।

धीरेंद्र सिंह दताल
निदेशक
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून।

काफल की मिठास

अशोक रावत
गढवाल प्रभारी

पहाड़ों का रस उपहार काफल के वृक्ष भी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। जंगलों में लग रही है निरन्तर आग ने इस वृक्ष के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया है। 'काफल पाको मिल नी चाखो' की धुन में मस्त रहने वाले पक्षी की आवाज भी अब सुनने को कम मिल रही है। वनों के अवैध कटान व जंगलों में लग रही निरंतर आग ने काफल की मिठास काफी कम कर दी है।

काफल का मौसम एक बार फिर जरूर आ गया है। काफल से भरी टोकरियां लिए गांव के लोग मुसाफिरों को बेचने फिर से निकल पड़े हैं। लेकिन अब वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। उल्लेखनीय है कि इसके छोटे बीच युक्त फल स्वादिष्ट तथा

एक चिड़िया चैत के महीने में 'काफल पाको मैं नि चाखो' कहती है जिसका अर्थ है कि काफल पक गए मैंने नहीं चखे, फिर एक दूसरी चिड़िया 'पूर्रे पुतई पुर्रे पुर' कहती है जिसका अर्थ है, पूरे हैं बेटी पूरे हैं।

जूस युवक होने के कारण बेहद पसंद किए जाते हैं। जंगल से फलों को तोड़कर ग्रामीण इन्हें बाजार तथा कस्बों में 200 से 300 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। एक पेड़ से 40 से 60 हजार प्रति वर्ष आए हो सकती है, लेकिन वृक्ष को पुनः रोपित करने के कोई प्रयास सामने नहीं आए हैं। काफल के फल को चार–पांच दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता यह अत्याधिक रस युक्त होता है तथा इसके बाद सड़ने लगता है। इसका रंग चमकदार लाल होता है, फल की तोड़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह है कि तोड़ने की अवधि बहुत ज्यादा होती है तथा एक पेड़ से कई चरणों में तुड़ाई होती है। जंगल में फलित अनेक पेड़ों से इस फल की तोड़ाई की लागत ही मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण है।

काफल के संबंध में गांवों में भांति–भांति के गीतों के साथ अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा इस प्रकार है जो बड़ी मार्मिक है, इसमें पहाड़ की गरीबी का दर्द छिपा है, कहा जाता है कि उत्तराखंड के गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसकी एक छोटी बेटी थी। दोनों एक–दूसरे का सहारा थी। आमदनी के लिए महिला के पास कुछ नहीं था थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, जो भरण पोषण के लिए काफी कम थी, किसी तरह ही घर चल पाता था। गर्मियों में जैसे ही काफल पकते महिला व उसकी पुत्री के चेहरे खिल उठते थे। महिला जंगल से कापल तोड़ कर लाती और उनको बाजार में बेचकर आती। एक बार वह जंगल गई और वहां से टोकरी भर कर काफल तोड़कर लाई। अभी सुबह का समय था, शाम को वह काफलों को बाजार में बेचने जाती। वह टोकरी लेकर आई और अपनी बेटी को बुलाकर कहा, ''बेटी में जंगल में चारा काट कर ला रही हूँ, तब तक तू इन काफलों की पहरेदारी करना। जंगल से आकर मैं तुझे भी कुछ काफल खाने को दूंगी, पर तब तक तू इन्हें खाना मत''।

छोटी सी लड़की उन काफलों की पहरेदारी करती रही, कई बार उसके मन में विचार आया कि कुछ खा लू, पर मां ने कहा है जब तक लौट कर ना आ जाऊं काफल मत खाना। लड़की अपनी जबां पर काबू कर बैठी रही। दिन में जब माँ घर वापस आई तो टोकरी का एक तिहाई भाग कम था और लड़की टोकरी के पास सो रही थी। माँ जो सुबह से काम में लगी थी और बेटी को बोल कर गई थी कि वापस आकर कुछ काफल दूंगी, वह बेटी की इस दृष्टता पर गुस्से से भर गई। उसने घास का गट्ठर एक तरफ फेंका और लड़की की पीठ पर जोरदार प्रहार कर दिया। माँ के एक ही प्रहार से बेटी वहीं पर ढेर हो गई। माँ ने उसे हिलाया–डुलाया पर तब तक उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे।

माँ उसके पास बैठी रोती रही, शाम होते–होते काफल की टोकरी फिर पूरी भर गई। तब महिला को समझ आया कि दिन की गर्मी से काफल मुरझा गये थे और शाम को ठंडी हवा लगते ही फिर ताजा हो गये। अब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी पुत्री के सदमे में मर गई।

कहा जाता है कि उस दिन के बाद से एक चिड़िया चैत के महीने में 'काफल पाको मैं नि चाखो' कहती है जिसका अर्थ है कि काफल पक गए मैंने नहीं चखे, फिर एक दूसरी चिड़िया 'पूर्रे पुतई पुर्रे पुर' कहती है जिसका अर्थ है, पूरे हैं बेटी पूरे हैं।

काफल पेट रोगों के लिए चमत्कारी रूप से लाभदायक है यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला सदाबहार वृक्ष है यह 13 सौ मीटर से 29 सौ मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। काफल के पेड़ के तनों की छाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सक इसे गर्माहट, उत्तेजक तथा खून रोकने के उपयोगी तथा यूनानी चिकित्सा में यह टॉनिक तथा गैस की बीमारी के उपचार में उपयोग में लाया जाता है। तने की छाल का सार, अदरक तथा दालचीनी का मिश्रण, डायरिया, अस्थमा, बुखार, टाइफाइड, पेचिश तथा फेफड़े की बीमारियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। छाल का पाउडर जुखाम, आंख की बीमारी तथा सर दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाता है। सड़े हुए घावों के लिए यह भी उपयोगी है। दांत दर्द के लिए छाल तथा कान दर्द के लिए छाल का तेल अत्याधिक उपयोगी है।

फैलती दुनिया, सिमटते सरोकार, सोशल मीडिया का मक्कड़जाल

हमारे समाज में हर कहीं, हर उम्र के लोगों में असुरक्षा और डिप्रेशन के मरीज व सार्वजनिक जीवन में जुनूनी हिंसक आचरण लगातार बढ़ रहे हैं।

आप सब गवाह हैं कि इन दिनों लगभग हर दूसरा दफ्तरकर्मी, राहगीर या वाहन चालक ही नहीं, फुटपाथ पर सामान बेचने खड़ा विक्रेता भी आसपास से बेखबर अपने सेलफोन पर बतियाता, स्मार्टफोन पर वीडियो क्लिप देखता या कान में खूंटी डाले संगीत सुनता रहता है। विडंबना देखिए कि जिस युग में बड़ी तादाद में सस्ते से सस्ते उपकरणों पर उपलब्ध नवीनतम एप्लीकेशंस देश के हर उम्र के नागरिक तक तमाम तरह की जरूरी सूचनाएं और जानकारियां 247 पहुंचा सकते हैं, पुलिस, मनोवैज्ञानिक और मीडिया हमको सोदाहरण यह भी दिखा रहे हैं कि हमारे समाज में हर कहीं, हर उम्र के लोगों में असुरक्षा और डिप्रेशन के मरीज व सार्वजनिक जीवन में जुनूनी हिंसक आचरण लगातार बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि बेरोकटोक बतकही, मनोरंजक कार्यक्रमों और संगीत के इस प्रसार के बावजूद तेजी से शहरी बन रहे हमारे युवा नागरिकों के बीच अजनबियत और तनाव कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। और परिवारों में फेसबुक या ट्विटर पर बड़ी सहजता से घुसकर सोशल मीडिया मंचों से दुनियाभर के लोगों की खबर लेने वालों के बीच दंपतियों, और अभिभावकों का बच्चों, बूढ़ों के साथ सहजता से उठना–बैठना और अंतरंग संवाद करना मिट रहा है।

उधर कला साहित्य जगत से जुड़े लोगों को भी शिकायत है कि नृत्य संगीत के इतने प्रचार के बाद भी उनके शास्त्रीय रूपों का सामूहिक रूप आनंद लेने अब युवा लोग पुरानी चौनभरी महफिलों में नहीं आते। जबकि वे कानफोडू साजों, जगर–मगर स्टेज इफेक्ट और अक्सर तेज रफ्तार लय पर नाच–नाचकर गाए जाने वाले अश्लील फिल्मी या पॉप संगीत के विशाल कार्यक्रमों के टिकट खरीदने को रात–रात भर कतार लगाते हैं। विराट स्टेडियमों या मैदानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से बने उनके मनपसंद आभासी नाच–गाने में उमड़ने वाले ये बच्चे या युवा टीवी रियलिटी शोज के मुरीद हैं। और उनके लिए संगीत

का मतलब चमत्कार प्रधान शोमैनशिप पर श्कूल अदा सहित स्टेज पर फूहड़ हरकतों का अंबार लगाना है। शहरों में बच्चे भी अब शाम को खेलने को बहुत कम बाहर जाते हैं। खेल का मतलब कुर्सी में पसरकर वीडियो गेम्स या फेसबुक सर्फिंग तक सीमित हो रहा है।

यह ठीक है कि हर जमाने के युवा अपने लिए अपनी तरह के कलात्मक और नागरिक सरोकार चाहते हैं। पर बात तब चिंताजनक बन जाती है कि कई जरूरी सामाजिक सरोकारों पर बहस न होने से घर भीतर अकेले अंतर्मुखी जीवन जी रहे नागरिक लोकतांत्रिक सरोकारों तथा आस–पड़ोस से कटकर असामाजिक तत्व बनते जा रहे हैं। रपटें यह भी हैं कि पुलिस ने घर में बंद मानसिक रूप से बीमार मृतप्राय लोगों को ताला तोड़कर निकाला, या दुर्गंध आने पर चौकीदार ने जब पुलिस को इत्तला दी तो अकेले में मर गए या मार दिए गए लोगों के शव बरामद किए गए। ऐसी खबरों पर आज बस कुछ दिन तक मीडिया में सर धुनाई और दोष का बंटवारा किया जाता है, फिर लोग अपने–अपने टीवी के किसी बेहूदा रियलिटी शो, या स्मार्टफोन, लैपटॉप पर उपलब्ध फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब की दुनिया में वापस दाखिल हो जाते हैं। युवा अपने जहन में परिवार या लोकतंत्र की नैतिकता को लेकर कोई बोझ नहीं पालते, न ही कैंपस में समानधर्मा लोगों को जुटाकर सामाजिक मुद्दों या सियासी विचारों पर सार्थक बहस व कार्रवाई शुरू करते हैं।

लोकतंत्र में सच्चा ज्ञान बटोरना रोजमर्रा की दुनिया में सशरीर घुसकर दुःख सहना और उसके लिए जोखिम उठाकर भी जिम्मेदारी महसूस करना होता है। पर आज का आम नागरिक जैसा कि कवि टीएस एलियट ने कहा था, बहुत दूर तक वास्तविकता का बोझ नहीं उठाता (ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी)। यही कारण है कि सुरसाकार बनते निजी सूचना साम्राज्य की जी–हुजूरी निरंतर एकाधिपत्य की तरफ लपकते राज समाज के तकलीफदेह ब्योरों से हमें दूर रखे हुए है। आज से तीस–चालीस बरस पहले जब दमघोंटू स्थितियां बनीं, संवेदनशील बड़े नेताओं और युवा नागरिकों के बीच लगातार संवाद कायम रहने से राजकीय प्रशासकीय दमनकारिता का सफल प्रतिकार संभव हुआ। पर आज आग की लपटों वाले टीवी संवाद के दौरान मतभेद सहना, कष्टकर होते हुए भी कई तरह की सचाइयों को स्वीकारना, दूसरे वक्ताओं की वैचारिक श्रेष्ठता और अपने ज्ञान की सीमा भी कभीकभार स्वीकार करना जैसे गुण गायब हो चले हैं। राजनीति या मीडिया दोनों की वे धंधई मर्यादायें टूट रही हैं, जो इन वैचारिक आदान–प्रदानों को अर्थमय और गंभीर बनाती थीं। काठ जैसे मुख से एक दलीय प्रवक्ता एंकर से कहता है, तुम्हारे चैनल का एजेंडा सरकार विरोधी है। और एंकर उतनी ही तल्खी से जवाब देती है कि जनाब, यह मेरा कार्यक्रम है। या तो आप इस बात के लिए माफी मांगिए या चलते बनिए। यह क्या है?

अहं को चोट पहुंचाने वाले झमेलों से बचने का विशिष्टजनों के पास आसान रास्ता है कि स्टूडियो से दनदनाते हुए निकल जाइए, फिर अपनी किसी पसंदीदा सोशल साइट में घुसकर फतवे जारी करा दीजिए। अगले दिन जब आरोपी चैनल पर खुफिया रेड होती है तो आप गंभीर चेहरे से कहिए कि कानून अपना काम करेगा। यह होने पर औसत युवा नवीनतम पॉप हिट्स के सेक्सी जलवों, या (खुद खूनी हिंसा का खतरा उठाए बिना) आबादी पर ड्रोन हवाई जहाजों के हमलों, जल डाकुओं से पिटते बंधकों और हॉलीवुड–बॉलीवुड के ताजा स्कैंडलों के नजारों का सीत्कारपूर्ण अवलोकन करने चल देता है। या फिर कान में आईपॉड की खूंटी डाल धमाकेदार संगीत की दीवार खींचकर खुद को बाहरी दुनिया से एकदम काट लेता है। यह जो नया सूचना विश्व हमारे अनचाहे ही रोज–रोज रचा जा रहा है, नासमझ हाथों में जाकर ऐसा खतरनाक सोच बना रहा है, जिसकी तहत सड़कों पर उतरी जुनूनी भीड़ का हाथ में कानून लेना कई लोगों को सही लगता है। क्या सूचना संचार क्रांति इसीलिए हुई थी कि दुनिया लोकतंत्रविमुख, मानवता विरोधी, एक दूसरे के सुख–दुःख से तटस्थ काठ बनती चली जाए? उपकरणों को दोष देना गलत होगा। बेजान मशीनों की नैतिकता तो उनको इस्तेमाल करने वाले राज समाज ही गढ़ते हैं। पर उनके दिलोदिमाग, उनकी नैतिकता कौन गढ़ रहा है, तो जो जवाब मिलता है वह बहुत आश्वस्त नहीं करता।

क्या यह विचार हमको कभी चिंतित करता है कि इस सबकी आखिरी परिणति क्या होगी? कुर्सी पर दूर बैठे अपने बंद सुरक्षित कमरों से पूरे देश–विश्व में सशस्त्र क्रांति और खूनी तख्तापलट का आवाहन और हर रंगत के नाटकीय क्रांतिकारियों की हौसला अफजाई करने वालों की इस दुनिया का अंत भी क्या प्रेमचंद की उस अमर कहानी शतरंज के खिलाड़ी के लखनऊ की ही तरह होगा, जहां दरबदर किए जा रहे बादशाह के लिए तो किसी की आंखों में दो बूंद आंसू नहीं थे, पर निर्जीव मोहरों की जंग जीतने के लिए पलक झपकते तलवारें म्यान से बाहर निकलीं और लाशें बिछ गईं।

राजनीति या मीडिया दोनों की वे धंधई मर्यादायें टूट रही हैं, जो इन वैचारिक आदान-प्रदानों को अर्थमय और गंभीर बनाती थीं। काठ जैसे मुख से एक दलीय प्रवक्ता एंकर से कहता है, तुम्हारे चैनल का एजेंडा सरकार विरोधी है।

धार्मिक बहुलता खुदा की ही मर्जी

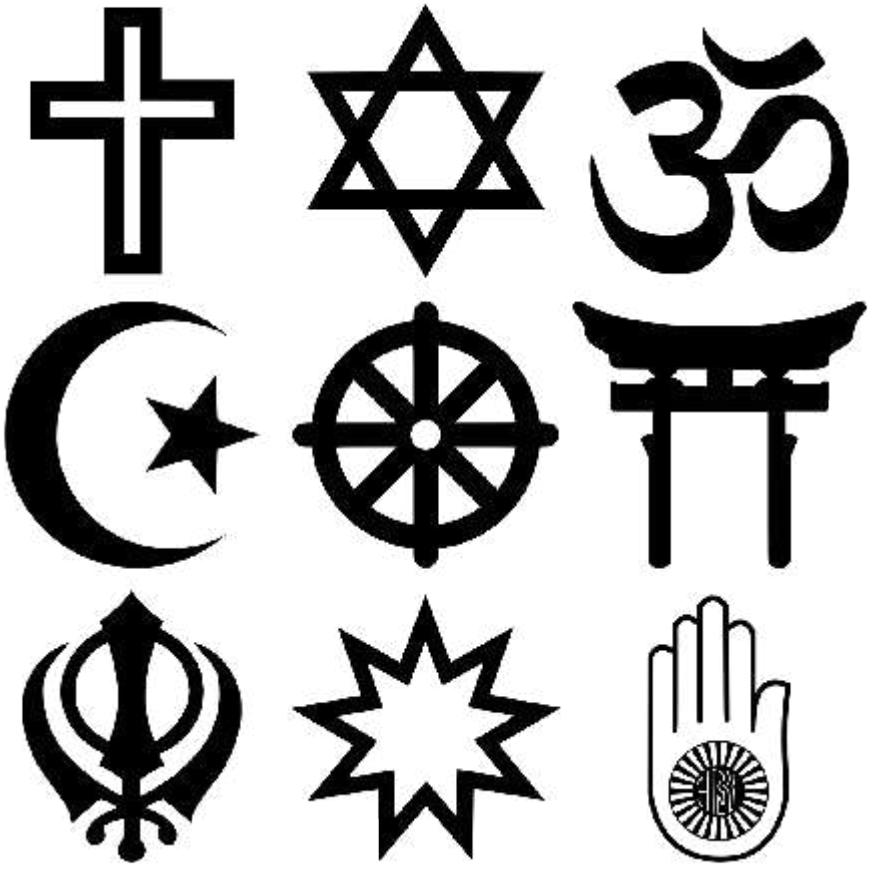

अमन रहमान

शताब्दियों तक एक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोगों ने एक दूसरे के धर्म को नकारा तथा निन्दा की, बल्कि कुछ-कुछ लोगों ने तो ज़बरदस्ती दूसरों का धर्म-परिवर्तन करवाया व न मानने वालों को अपने धर्म से निकाल तक दिया।

देश के नौजवान हमेशा यह सवाल अवश्य पूछते हैं कि अगर ईश्वर सिर्फ एक है तो इतने सारे फिरके क्यों हैं। यह सवाल बार-बार धार्मिक गुरुओं से पूछा जाता रहा है।

कुरान के अनुसार अल्लाह ने हम सबको एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए एक धार्मिक समुदाय सृजित किया, किन्तु उसकी मंशा यह नहीं थी कि वह हमें इस धर्म के प्रति आस्था को परखे। अर्थात 'अगर अल्लाह ने ऐसा चाहा होता तो आपको एक इंसा नहीं बनाया होता, किन्तु उसकी योजना है कि वो आपको परखे और देखे कि जो जिसने आपको बख्शा है, उसके प्रति आप कैसा नजरिया रखते हैं?, क्योंकि उसने आपको नस्ल के रूप में पूरी खुशीसियातों से भरा है। आपका मक़सद उस अल्लाह को खुश करना होगा जो आपको उन सभी मामलों की सच्चाई दिखलाएगा जिनमें कोई विवाद है।' (कुरान 5:48)

इसका यह मतलब है कि धार्मिक अनेकता खुदा की मर्जी है, किन्तु शताब्दियों तक एक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोगों ने एक दूसरे के धर्म को नकारा तथा निन्दा की, बल्कि कुछ-कुछ लोगों ने तो ज़बरदस्ती दूसरों का धर्म-परिवर्तन करवाया व न मानने वालों को अपने धर्म से निकाल तक दिया। एक ईश्वर को मानने वाले एक ही खुदा की

इबादत करते हैं तथा इस एक ईश्वरीय धर्म को मानने वाले सभी पैगम्बर एक ही खुदा से प्रभावित हैं।

सवाल उठता है कि यह धार्मिक असहिश्णुता कैसे आई और हम इसे अब्राहिमी धर्मों से किस प्रकार अलग-थलग कर सकते हैं। यूनानी दर्षनशास्त्र के अनुसार, सत्य कभी न बदलने वाला अपरिवर्तनीय व सार्वभौमिक है। इस बात ने पवित्र धर्म-ग्रन्थों के विद्वानों को मध्यकालीन युग में हमेषा प्रभावित किया, जिनका मानना था कि ज़्यादातर धर्म-ग्रन्थ 'षून्य' पर आधारित खेल हैं अर्थात् अधिक सच्चाई इन ग्रन्थों में निहित है, न कि उनकी व्याख्या करने वाले विद्वानों में, जो कि विभिन्न धर्म-ग्रन्थों को एक दूसरे के पूरक न मानते हुए, इन्हें एक दूसरे के विरोधी मानते हैं तथा अन्य धर्मो के धर्म-ग्रन्थों को झूठा करार देते हैं।

अगर इस अलग-अलग फिरके वाले संसार में धर्म का उपयोग शान्ति हेतु करना है तो लोगों को शून्य पर आधारित विचारधारा को नकारना होगा एवं बहुलवादी शिक्षाएं जो विभिन्न धर्म-ग्रन्थों में पहले से विद्यमान हैं, का विकास करना होगा।

कुरान के अनुसार

प्रत्येक समुदाय के लिए हमने इबादत की पूरी प्रक्रिया को इज़ाद किया है जिसे उन्हें मानना होता है। अतः उन्हें आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ने देना, बल्कि

अपने लोगों को यह बताना होगा कि इन्तहा के दिन खुदा खुद यह निर्णय लेगा कि कौन एक दूसरे के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता। इसी प्रकार कई अन्य कथन हैं जिनसे पता चलता है कि मतों के भेद, अल्लाह की मर्ज़ी है और वह हमारा इम्तिहान ले रहा है।

अच्छे और बुरे के बीच चुनना प्रत्येक यकीन रखने वाला व नायकीनी चाहता है। जैसे एक तरफ 'आस्तिक' ईश्वर की प्रत्येक बात में विश्वास करते हैं, किन्तु अगर हमें दया, करूणा व शान्ति को आंकना है तो हमें इसे बहुलवादी परिपेक्ष्य में देखना होगा न कि सापेक्षिक सन्दर्भ में। उदाहरण के लिए, यह मानना कि प्रकाश तरंगों में यात्रा करता है, सत्य है।

यह भी सत्य है कि प्रकाश 'फोटोन' नामक अनगिनत कणों से बना है, किन्तु उससे भी अधिक सत्य यह है कि प्रकाश 'लहर' व 'पार्टिकल' दोनों ही हैं और किसी खास वक्त में वह कैसे दिखता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला उस समय किस ढांचे (ज़रिए) का प्रयोग कर रहा है। सत्य जानने की जटिलता अल्लाह की इच्छा है, इसीलिए कह सकते हैं कि वह मोमिनों की दया, करूणा व अमनपरस्ती को हमेशा परखता रहता है।

उत्तराखण्ड में नशे का फैलता जाल

युवकों को स्मैक चरस से लेकर अन्य सामान नशा तस्कर उपलब्ध करा रहे है। जिससे चलते छात्रों का भविष्य अंधकार मय बनने के आसार है।

प्रदेश की राजधानी देहरादून सहित आसपास के पूरे क्षेत्र में नशा तस्करों ने अपना जाल पूरी तरह से फैला लिया है। जिसके चलते दून का युवा नशे की गिफ्त में फंसता चला जा रहा है। इस मामले में पुलिस की कार्यवाही नशा तस्करो पे शिकंजा कसने के मामले में पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है। जिससे युवाओं का का भविष्य नशे की गर्त में समाता चला जा रहा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में लगभग दो लाख विद्याथी दून में किसी न किसी रूप से शिक्षा ग्रहण करने आ आते है। जोकि अपने परिवार से दूर रहकर दून में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। बाहर से आने वाले अधिकांश युवा नशा तस्करों के निशाने पर आ रहे है। युवकों को स्मैक चरस से लेकर अन्य सामान नशा तस्कर उपलब्ध करा रहे है। जिससे चलते छात्रों का भविष्य अंधकार मय बनने के आसार है। सबसे अधिक नशा तस्कर दून के प्रेमनगर इलाके से लेकर विकासनगर तक सक्रिय है। क्योंकि अधिकाश प्राईवेट शिक्षण संस्था इन्ही इलाकों में मौजूद है। किन्तु नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही नामाफी साबित हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जनपदो में भी नशाखोरी लगातार बढ रही है।

उत्तराखंड में नशाखोरी की जड़ें तेजी से फैलती जा रही हैं। युवा पीढ़ी नशे के दल–दल में फंसती जा रही है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण ही अपराध भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने यदि युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो स्थिति भयावह हो सकती है। नशे से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। नशे के कारण शांत वादियों वाला यह प्रदेश अशांत होता जा रहा है।

पंजाब की राह पर आगे बढ़ रहे उत्तराखंड में पुलिस ने एक साल के भीतर सात करोड़ की नशे की सामग्री बरामद की। यह आंकड़ा अब तक पकड़े गए नशे के किसी भी साल से ज्यादा है। इस दौरान 934 मुकदमे और 980 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जबकि अंडर ग्राउंड कारोबार फैला रहे गिरोह पुलिस की नजर से दूर हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर 13 जिलों में एक साल के भीतर विभिन्न नशे के कारोबार में लिप्त पाए गए 980 लोगों पर 934 मुकदमे दर्ज किए गए। इस दौरान प्रदेश से कम और दूसरे राज्यों से नाता रखने वालों की संख्या ज्यादा पाई गई। बॉर्डर से लगे शहरों एवं तीन बड़े जिले देहरादून, ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार में नशाखोरी में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। जबकि सीमांत जनपद उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल में चल रहे नशे के कारोबार ने भी पुलिस की चिंता बढ़ाई। नशे के इस धंधे में सौदागार से लेकर खरीदारों में युवाओं की संख्या 70 फीसदी थी। इसमें भी स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट संस्थानों में डिग्री, डिप्लोमा लेने वाले युवा शामिल बताए गए। पूरे साल चले अभियान के दौरान पुलिस ने 974 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जबकि 99 अभी भी फरार चल रहे हैं। बरामद नशे की सामग्री से साफ है कि प्रदेश में चरस, स्मैक, डोडा, भांग और अफीम के बाद नशीली दवाओं का सबसे ज्यादा कारोबार है। नशाखोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से रोका जा सके। अपराधों में नशा एक बड़ा कारण है।

सिर्फ डमी बनकर रह गया ऊर्दू अकादमी

क्या हाईकोर्ट के फटकार से टूटेगी त्रिवेन्द्र सरकार की नींद?

ऐसा लग रहा है कि उत्तराखण्ड सरकार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नहीं बल्कि हाईकोर्ट चल रही है। क्योंकि बिना हाईकोर्ट के दखल दिये कोई भी कार्य उत्तराखण्ड में होता नहीं दिख रहा, चाहे वह अतिक्रमण हटाने का मामला हो या फिर किसी बोर्ड या संस्था में कार्यकारिणी विस्तार करने का मामला हो।

ऐसा ही मामला जून माह में मदरसा बोर्ड को लेकर हल्द्वानी के फैजान अल्वी के द्वारा एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली गई जिसमें पूछा गया था कि मदरसा बोर्ड में अभी तक कोई भी कार्यकारणी क्यों नहीं बनाई गई। हाईकार्ट ने याचिका का संज्ञान लेते हुये सरकार से जवाब मांगा की आखिर अभी तक मदरसा बोर्ड की कार्यकारणी समिति तैयार क्यों नहीं की गई। जिस पर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर सरकार को फटकार लगाते हुये 3 दिन के अन्दर कार्यसमिति को गठित करने को कहा। इसी आनन-फानन में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बिलाल रहमान को चुन लिया गया जिसका सरकार को काफी विरोध झेलने को मिला। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया था, उसमें में हरिद्वार के राव सराफत को वक्फ बोर्ड का सदस्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण लगभग छह महिने बाद ही इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

ठीक उसी तरह एक और मामला ऊर्दू अकादमी का है जिसे 2013 में बना तो दिया गया था लेकिन उसके कार्यकारिणी समिति का विस्तार अब तक नहीं किया गया और वर्ष 2018 में इसे भाषा संस्थान अकादमी के अन्तर्गत लाया गया। इसके साथ ही हिन्दी, पंजाबी, और लोकभाषा को भी जोड़ा गया और कार्यकारिणी सदस्य के लिये जिओ भी पारित कर दिया, मगर अभी तक इसमें कार्यकारिणी सदस्य नहीं चुने गये। भाषा संस्थान सिर्फ डमी बनकर रह गई है। अब लगता है कि जैसे इस पर भी हाईकोर्ट अपने संज्ञान में नहीं लेगी तब तक त्रिवेन्द्र सरकार ऊर्दू अकादमी का कार्यकारिणी गठित नहीं करेगी। अब सवाल यह उठता है कि हर मसले को जब हाईकोर्ट के दखल के बाद ही संज्ञान लिया जायेगा तो त्रिवेन्द्र सरकार का क्या काम रह गया है?

वन विभाग ग्रामीण और अग्नि त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए वन

प्रकाश चन्द्र उनियाल
संवाददाता

हमें आज भी समझ में नहीं आता कि लाखों सरकारी प्रयत्नों के पश्चात भी वनों के जलने की घटनाएं बरकरार है। सरकार द्वारा सारा बजट सुरक्षा हेतु मुहैया करवा दिया जाता है, तत्पश्चात भी समस्याएं नागिन की तरह यथावत बरकरार रहती है। हमें देखना है ऐसे कौन से हालात और परिस्थितियां हैं जिससे समस्याएं स्प्रिंग की तरह अपनी पुनरावृत्ति कर लेती है।

उदासीन होते ग्रामीण :- ग्रामीण जीवन में वनों का सदा से रिश्ता और प्रबल महत्व रहा है। जानवरों में गाय, बैल, बकरियों को वनों में चराने ले जाना, वनों से घास काटना, वनो से लकड़ियों को जागृत करना, घरो की सुरक्षा के लिए लकड़ियों को काटकर लाना और अपनी सुरक्षा करना।

किंतु वर्तमान समय में वन विभाग द्वारा ऐसे कानून पारित कर दिए गए हैं, जिन्होंने ग्रामीणों का जीना हराम कर दिया है। अपनी इच्छा से एक गाय के लिए घास काट कर नहीं ला सकते, बकरियां जंगलों में नहीं चुगा सकते इन्हीं कठिन परिस्थिति

ग्रामीणों को घास एवं झाड़ी की लकड़ियों को निकालने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता कानून की मर्यादा के दायरे ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए।

में एक डंडा भी नहीं काट सकते। ग्रामीणों के हितों की अनदेखी करना ही वन विभाग को एक सदाबहार सिरदर्द बन गया है।

वन विभाग इस विषय में अनुमान लगाने में बिल्कुल नाकाम रहा है कि जंगलों के जलने से अधिक हानि होती है या ग्रामीणों के लघु निजी उपयोग से।

दोनों को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को घास एवं झाड़ी की लकड़ियों को निकालने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता कानून की मर्यादा के दायरे ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में सती प्रथा चलती थी कि पति को मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी चिता में जलना पड़ता था, ऐसा लगता है जब वनों को जलते हुए देखता हूं तो इनका साया सिर से हट गया है, अब यह अनाथ हो चुके हैं। आप तो इन्हें जलना ही जलना है, सरकार इसके लिए सक्षम कानून और सक्षम उपाय नहीं ला पा रही है।

सरकार और सक्षमता :- अब तो देश को आजाद हुए बहुत समय हो गया राष्ट्रीय क्षमता में देश सबल है, धन का अभाव भी नहीं है, किंतु आग बुझाने वाले सक्षम उपकरणों को खरीदने में विभाग क्यों उदासीन है? आधुनिक समय में छोटे से लेकर बड़े तक उपकरण हैं जिनसे आग को बड़ी आसानी से काबू किया जा सकता है फिर लापरवाही क्यों अपनाई जाती है। वन विभाग के बदलते कानून के सामने ग्रामीणों के सारे रोजगार और अधिकार छिनते चले गए, घास, लकड़ी, चारागाह, पशुपालन आदि अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए वनों पर आधारित है। धीरे-धीरे इनके हाथ से यह सुविधाएं निकल गई। भवन निर्माण जैसे विषयों में ग्रामीणों को आसानी से सुविधाएं उपलब्ध होने चाहिए, आजीविका चलाने के लिए घास और जलाऊ लकड़ी की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए, जिससे गांव के प्रति उदासीनता महसूस ना हो और गांव छोड़ पलायन ना करना पड़े।

विभागीय कमजोरियां भी इसमें कम नहीं :- विभाग संरक्षण के प्रति काफी हद तक अनदेखी करते हैं, वनों के मध्य विद्युत तारों का गुजरना, यह एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। वर्तमान में पंच केबिल की सुविधा उपलब्ध हो गई है, यदि वनों के मध्य गुजरने वाले पंच केबिल हो तो बिजली द्वारा भय समाप्त हो जायेगा।

वृक्षारोपण कार्यो का पुरा ना होना :- वन विभाग द्वारा कई ऐसे कारण हैं जो पूर्ण नहीं होने वाले। अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए विभागीय लोग आग लगाने जैसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं।

लकड़ी की अनियमित बिक्री :- ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वन विभाग कर्मी कभी आगजनी की घटनाएं कर बैठते हैं।

वनों में अनियमित पेड़ों का काटा जानाः- विभागीय कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की इंक्वायरी होने के भय से आग लगाने की घटनाएं सामने आती है। जनाक्रोश एवं अधिकारियों का भय सिर पर सदा सवार रहता है, इस कारण वह कुछ भी कर बैठते हैं।

वनों में झाड़ी एवं खरपतवार की भारी मात्रा में इकट्ठा होने से जंगलों में आग लग जाती है।

जागरूकता की कमीः- हमे लोगों को जागरूक करना होगा कि बीड़ी, सिगरेट पीने के पश्चात इनको बुझा दे, जंगलों की तरफ ना फेंके, इससे भी आग लगने की घटनाएं होती हैं।

संसाधनों का अभावः- वर्तमान अर्थव्यवस्था में धन का कहीं पर भी अभाव नहीं है तो फिर छोटी फायर वॉटर टैंकर और धुआं छोड़ने वाली मशीनें ग्रामीणों को उपलब्धियों क्यों नहीं कराई जाती।

विभाग द्वारा वनों से जलने से जितने राजस्व की हानि होती है, आकलन किया जाता है यदि उसका 10 प्रतिशत सुविधा एवं छूट ग्रामीणों को ही दे दी जाए तो वनो का जलना काफी हद तक रोका जा सकता है।

उत्तराखंड शासन
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून द्वारा अनुसूचित जाति के एकल कलाकारों को पारंपरिक वाद्ययंत्र (ढोल–दमाँऊ, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल–तलवार आदि) निःशुल्क प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों को पारम्परिक/लोक कलाकारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 15 सितंबर 2019 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

1– किसी कलाकार को आजीवन वाद्ययंत्र एक बार ही दिया जायेगा।

2– आवेदक की मासिक आय 2000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय संबंधी प्रमाण–पत्र तहसीलदार स्तर से लिया जाना आवश्यक होगा।

3– एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।

4– परम्परागत वादक परिवार (बाजगीय) के कलाकार को वाद्ययंत्र दिए जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

5– आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6– यदि किसी आवेदक को संस्कृति विभाग की किसी अन्य योजना में कोई आर्थिक सहायता अथवा वाद्ययंत्र प्राप्त हुये हो, तो उसे यह सुविधा/लाभ अनुमन्य नहीं होगा, सम्बन्धित कलाकार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसे विभाग की अन्य योजना से कोई अनुदान अथवा वाद्ययंत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कलाकारों को वाद्ययंत्र दिये जाने की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत की जायेगी। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट– निर्धारित तिथि 30 सितंबर 2019 तक आवेदन पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायें। निर्धारित तिथि पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड

अनुसूचित जाति के परम्परागत/पेशेवर कलाकारों को निःशुल्क वाद्ययंत्र दिये जाने हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

1–आवेदक कलाकार का नाम.....(मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

2–पिता/पति का नाम.....

3–आवेदक की मासिक आयु.....(शैक्षिक प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्ट्रर की छायाप्रति संलग्न करें)

4–जाति.....(सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है)

5–आवेदक की मासिक आय ₹ .....(₹ .....) (आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र तहसीलदार स्तर से निर्गत हो, संलग्न करना आवश्यक है)

6–बी0पी0एल0 कार्ड धारक खण्ड विकास अधिकारी से बी0पी0एल0 कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7–आवेदक का पूरा पता–ग्राम.....पो0ओ0.....विकासखण्ड.....जनपद.....

8–परम्परागत वाद्ययंत्र का नाम जिसमे आवेदक निपुण हो.....

9–यदि आवेदक परम्परागत वादक परिवार (बाजगीय) से तालुक रखते हैं (तो पूरण दें).....

10–वाद्ययंत्र का नाम जिसे निःशुल्क प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो.....

11–मोबाइल नं0/दूरभाष सं0.....

शपथ पत्र

मैं.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे संस्कृति विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग की किसी अन्य योजना से कोई आर्थिक सहायता/अनुदान एवं पूर्व में वाद्ययंत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन, देहरादून

एन0आर0एल0एम0 प्रगति						
एन0आर0एल0एम0 भौतिक प्रगति						
क्र0 सं0	विवरण	प्रगति वित्तीय वर्ष 2018–19		प्रगति वित्तीय वर्ष 2019–20		कर्मिक प्रगति
		वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति	
1	समूह गठन	8000	9633	10000	1268	23155
2	आर0एफ	6476	6562	8500	833	15652
3	सी0आई0एफ0	2258	2317	10000	854	4939
4	वी0ओ0	800	753	1000	59	1143
5	सी0एल0एफ0	20	22	60	5	39
6	सी0सी0एल0	5641	3247	7610	325	5543
7	एम0सी0पी0	8655	8879	8000	793	12481

एन0आर0एल0एम0 वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक धनराशि लाख में	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्ती	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय	प्रतिशत व्यय
2018-19	122.38	3217.42	273.62	67.27	3780.03	3627.2	96%
2019-20	743.12	1842.99	168.15	3.04	2757.3	1683.21	61.04%

डॉ0 राम बिलास यादव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मा0 कृषि मंत्री/अध्यक्ष उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से 15 अगस्त 2019 की शुभकामनायें।

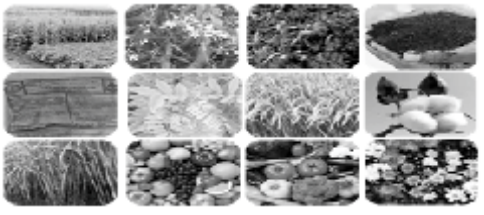

Uttarakhand Organic Commodity Board

Organic Vegetable Haat
जैविक सब्जी हॉट

1 स्थान– सर्वे चौक सरस विपणन केन्द्र प्रत्येक रविवार (प्रातः 10 से 02 बजे)

2 स्थान– किसान भवन, रिंग रोड़, नेहरूग्राम देहरादून (सांय 03 बजे 07 बजे)

जैविक उत्पादक समूह द्वारा उत्पादित जैविक सब्जियां– फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, तोराई, कद्दू, आलू, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, पनीर, मट्ठा, पर्वतीय दाले व मसालें इत्यादि उपलब्ध है।

द्वारा

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद

किसान भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड, नेहरूग्राम, देहरादून, दूरभाष : 0135–2662770 फैक्स : 0135–2662771

Web : www.organicuttarakhand.in E-mail- uocb_dehradun@yahoo.co.uk

सम्पर्क नम्बर– विपणन प्रबन्धक– 7248485727, सहायक विपणन प्रबन्धक– 9411377943, कड़ी आपूर्ति प्रेरक– 7409889593

नैनी झील : नैनीताल का मुख्य आकर्षण

नैनीताल में पानी न मिलने पर ऋषि अत्री, पुलस्त्य और पुलह ने मानसरोवर झील से लाकर भरा था यहां पानी

नैनी झील नैनीताल का मुख्य आकर्षण है। इस खूबसूरत झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए लाखों देशी-विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। रात के समय जब चारों ओर बल्बों की रोशनी होती है तब तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। झील के उत्तरी किनारे को मल्लीताल और दक्षिणी किनारे को तल्लीताल करते हैं। यहां एक पुल है जहां गांधीजी की प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस है। यह विश्व का एकमात्र पुल है जहां पोस्ट ऑफिस है। इसी पुल पर बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी है। झील के दोनों किनारों पर बहुत सी दुकानें और खरीदारी केंद्र हैं जहां बहुत भीड़भाड़ रहती है।

नदी के उत्तरी छोर पर नैना देवी मंदिर है। नैनीताल में तल्लीताल डाट से मछलियों का झुंड उनको खाना आदि देने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस झील के

तट पर नैनीताल नगर स्थित है। पर्यटकों के लिए यह सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है। खासतौर से तब जब सूरज की किरणें पूरी झील को अपनी आगोश में ले लेती हैं। यह चारों तरफ से सात पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैनीताल में नौकायें और पैडलिंग का भी आनंद उठाया जा सकता है। मुख्य शहर से तकरीबन ढाई किमी दूर बनी नैनी झील तक पहुँचने के लिए केवल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। कहा जाता है कि जब अत्री, पुलस्त्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्डा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर उसमें भरा। इस झील के बारे में कहा जाता है यहां डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी से मिलता है। यह झील 64 शक्ति पीठों में से एक है।

विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी

जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में पहुंचे थे

फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व की धरोहरों की सूची में शामिल किया गया। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्डसवर्थ ने लगाया था, जो संयोग से 1931 में अपने कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे।

इसकी बेइंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ 1937 में इस घाटी में वापस आये और, 1938 में वैली ऑफ फ्लॉवर्स नाम से एक किताब प्रकाशित करवायी। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों या फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है। नवम्बर से मई माह के मध्य घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है। जुलाई एवं अगस्त माह के दौरान एल्पाइन जड़ी की छाल की पंखुडियों में रंग छिपे रहते हैं।

यहाँ पाये जाने वाले फूलों के पौधों में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्श, गेंदा, प्रिभुला, पोटेन्टिला, जिउम, तारक, लिलियम, हिमालयी नीला पोस्त, बछनाग, डेलफिनियम, रानुनकुलस, कोरिडालिस, इन्डुला, सौसुरिया, कम्पानुला, पेडिक्युलरिस, मोरिना, इम्पेटिनस, बिस्टोरटा, लिगुलारिया, अनाफलिस, सैक्सिफागा, लोबिलिया, थर्मोपसिस, ट्रौलियस, एक्युलेगिया, कोडोनोपसिस, डैक्टाइलोरहिज्म, साइप्रिपेडियम, स्ट्राबेरी एवं रोडोडियोड्रान आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। यूनेस्को ने नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह उद्यान 87.50 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। किंवदंती है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पहुंचे थे।

गूगल सर्च पर फिर से टॉप पर रहीं सनी लियोनी

बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद एक्ट्रेस सनी लियोनी को अपनी पुरानी छवि से निकलने में काफी मदद मिली। अपनी एक्टिंग और डांस के टैलेंट से सनी लियोन ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। सनी बिना किसी शक सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रेटी हैं। इस साल भी भारत में गूगल सर्च में अगस्त के पहले हफ्ते तक सबसे अधिक ढूंढे जाने वाली हस्तियों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान को पीछे छोड़ते हुए सनी शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं।

गूगल ट्रेंड्स एनालिटिक्स के अनुसार, सनी से जुड़ी ज्यादातर खोजें उनके वीडियो के संबंध में हैं, इसके अलावा उनकी बायोपिक सीरीज 'करणजीत कौर : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन' को भी लोगों ने ढूंढा है। इसके अलावा सनी से जुड़े अधिकतर सर्च ट्रेंड्स बताते है कि उन्हें सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे मणिपुर और असम में खोजा गया।

इस खबर पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी टीम ने मुझे इस बात की जानकारी दी और मैं इसका श्रेय अपने फैंस को देना चाहूंगी, जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। यह एक महान भावना है। पिछले साल भी भारत में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले हस्तियों की इस सूची में सनी पहले स्थान पर रही थीं।

माफ कीजिए मैं देशभक्त हूं

प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजिल्स में ब्यूटीकॉन फेस्टिवल 2019 में मौजूद थीं। इसी दौरान ने एक महिला ने उनसे सवाल किया कि यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर होने के बावजूद भी वे युद्ध को प्रोत्साहन दे रही थीं। लेकिन प्रियंका ने खुद को देशभक्त कहा और सवाल का जवाब दिया, जिसके बाद लगातार उनकी प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि जिस ट्वीट को लेकर उस महिला ने सवाल किया था वह ट्वीट बालाकोट हवाई हमले के बाद किया गया था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में महिला को प्रियंका चोपड़ा से कह रही है– 'आप शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर हैं और आप पाकिस्तान में परमाणु युद्ध को प्रोत्साहित कर रही हैं। यह कोई तरीका नहीं है जो आपने बताया... एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे जैसे लाखों लोग आपके समर्थक हैं।

प्रियंका ने उस महिला को जवाब देते हुए कहा– मेरे पाकिस्तान से कई दोस्त हैं और मैं भारत से हूं। युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं वास्तव में पसंद करती हूं, लेकिन मैं देशभक्त हूं। इसलिए मुझे खेद है कि अगर मैं उन लोगों की भावनाओं को आहत करती हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं, हमें बीच एक रास्ता है जिस पर हम सभी को चलना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप भी करते हैं। जिस तरह से तुम अभी मेरे पास आए हो, चिल्लाओ मत। हम सब प्यार के लिए यहां हैं।

नेशनल अवार्ड जीतने का अभी तक विश्वास नहीं हो रहा

फिल्म 'अंधाधुध' के लिए आयुष्मान खुराना को नेशनल अवार्ड मिला है। आयुष्मान यह अवॉर्ड विक्की कौशल के साथ शेयर कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना इस सम्मान से बेहद खुश हैं, वहीं यह भी मानते हैं कि इस सम्मान के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वह पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर न छोड़ें। मुंबई में आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म 'ड्रीमगर्ल' का ट्रेलर रिलीज किया गया। इसी दौरान आयुष्मान खुराना ने बताया कि अपनी फिल्म का शूट कर रहे थे, जिस वक्त नेशनल अवॉर्ड की अनाउंसमेंट किया गया।

आयुष्मान आगे बताते हैं कि अब तक उन्हें कई अवॉर्ड मिल चुके हैं लेकिन

नेशनल अवॉर्ड को पाना एक बहुत बड़ी बात है। यह बिलकुल उसी तरह है जैसे बोर्ड के एग्जाम में बच्चे के नंबर दूसरों को पहले पता चल जाते हैं। आयुष्मान शूट कर रहे थे और जब अपना शॉट देकर वापस आए तो उनके फोन में 40 मिस कॉल और ढेर सारे मैसेज भेज थे। मैसेज देखकर वह घबरा गए हालांकि मैसेजेस पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें फिल्म के लिए अवॉर्ड मिला है जिसकी उन्हें बहुत खुशी हुई।

विक्की कौशल के साथ अवॉर्ड साझा करने पर आयुष्मान कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने विक्की कौशल से बात की। आयुष्मान कहते हैं कि विक्की बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और अच्छी बात यह है कि वह दोनों पंजाब से आते हैं। आयुष्मान खुराना अवार्ड मिलने के बाद इंडस्ट्री और फैंस से मिले प्यार, मैसेजेस, कॉल के लिए आभार प्रकट करते हैं। आयुष्मान इतने खुश हैं कि उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला है।

मैं टाईम विटनेस की सदस्यता ले रहा/रही हूं।

नाम – श्री/श्रीमती/कुमारी.....जन्म तिथि.....

पता.....

.....राज्य.....

फोन (निवास).....मोबाईल.....ई–मेल.....

कृपया Time Witness के नाम का डी.डी. या चेक नं.....तिथि.....प्राप्त करें।

बैंक का नाम.....

कृपया इस फार्म को भरकर डी.डी. या चेक के साथ हमे इस पते पर भेंजे।

टाईम विटनेस, मासिक पत्रिका

शर्मा कॉलोनी, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून।

7409293012, 7078188479

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	बचत	सब्सक्रिप्शन मूल्य
1 वर्ष	12	180	30.00	150
2 वर्ष	24	360	60	300
3 वर्ष	36	540	110	430
4 वर्ष	48	720	200	520

नियम व शर्तें

1. यह योजना केवल भारत में ही मान्य है।
2. पत्रिका साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी तथा डाक गुम हो जाने पर जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी। सूचना प्राप्त होने पर यदि वह अंक उपलब्ध रहता है तो पुनः निशुल्क प्रेषित कर दिया जायेगा।,
3. कूरियर रजि. डाक से मंगवाने के लिए ग्राहक का कूरियर रजि. डाक खर्च अतिरिक्त वहन करना होगा।
4 सभी विवादों का निपटारा देहरादून (उत्तराखण्ड) न्यायालय के अधीन होगा।

सभी देश व प्रदेश वासियों को
ईद-उल-अजहा
स्वतंत्रता दिवस
एवं
रक्षाबंधन
की
हार्दिक शुभकामनाएं
बिलाल रहमान
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड
प्रदेश संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

HIMALAYA MOTORS
की ओर से सभी देश व प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
LUBRICANTS, SPARE PARTS
SEAT COVERS & ACCESSORIES
Shimla bypass road,
Pithuwala, Dehradun
9058374488, 9149052812

मनमोहन कण्डवाल
अध्यक्ष
बार एसोसिएशन
अनिल शर्मा
सचिव
बार एसोसिएशन
देहरादून बार एसोसिएशन की ओर से
सभी देश व प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
व रक्षाबंधन
की हार्दिक शुभकामनाएं

सभी देश व प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
एवं
रक्षाबंधन
की
हार्दिक शुभकामनाएं
सुनीता प्रकाश
अधिवक्ता एवं समाजसेवी
संचालिका : एस.पी. 7
स्व. श्रीमती बंचीदेवी एवं
श्री श्यामलाल जी सर्वोदय केंद्र, देहरादून

सभी देश व प्रदेश वासियों को
ईद-उल-अजहा
स्वतंत्रता दिवस
एवं
रक्षाबंधन
की
दिली मुबारकबाद
आर.ए. खान
निदेशक
प्रयाग आई.ए.एस अकादमी

सभी प्रदेशवासियों को
ईद-उल-अजहा
स्वतंत्रता दिवस
व रक्षाबंधन
की हार्दिक शुभकामनाएं
इरशाद अली
पूर्व ग्राम प्रधान, मेहूवाला माफी
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उत्तराखण्ड